मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं नई दिल्ली से एक साथ प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र

हमारा उद्देश्य सेवा समर्पण जनकल्याण

एक सत बुलेटिन

E-mail: eksatbulletin@gmail.com | जबलपुर, बुधवार 23 सितंबर 2026 | वर्ष-07, अंक-326, पृष्ठ-08, मूल्य- दो रुपए | Website: www.eksatbulletin.in

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेंगलुरु में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) ग्वालियर में निवेश के लिए निवेशकों से किया संवाद

डिजाइन इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के संकल्प को साकार करना है लक्ष्य

एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश आधुनिक तकनीक और निवेश के लिए देश का सबसे अनुकूल राज्य है। देश के हृदय स्थल में स्थित मध्यप्रदेश को अपने केंद्रीय भौगोलिक स्थान, मजबूत बुनियादी ढांचे और सरप्लस बिजली का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त है।

राज्य में उद्योग अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि विगत पौने तीन वर्षों में लगभग सभी सेक्टरों में 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्य की धरती पर उतर चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह बात बेंगलुरु में ग्वालियर में विकसित किए जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) में निवेश आकर्षित करने के लिए आयोजित राउंड टेबल बैठक में निवेशकों से संवाद के दौरान कही।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि समय को सही अवसर पर पहचान कर निर्णय लेना ही एक सफल उद्यमी की पहचान है। दिल्ली और मुंबई के रोड-शो में निवेशकों से मिले सकारात्मक प्रतिसाद से स्पष्ट है कि उद्योग जगत का भरोसा मध्यप्रदेश पर निरंतर मजबूत हुआ है। निवेशकों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश करने का यही सही समय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहयोग से केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश शासन ने मिलकर टेलीकॉम सेक्टर में एक नया और ऐतिहासिक मॉडल स्थापित किया है। ग्वालियर में बन रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इसी साझी सोच का प्रतिफल है।

उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में भूमि सीमित है, इसलिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आने वाले निवेशकों को विशेष लाभ मिलेगा, जबकि आगामी चरणों में नियम व शर्तें भिन्न होंगी। इस औद्योगिक पार्क में एक ही स्थान पर डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से लेकर एक्सपोर्ट तक की पूरी वैल्यू चेन का निर्माण होगा। यहां सिम से लेकर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के उपकरण, 5-जी और 6-जी के उपकरण, ऑप्टिकल फायबर और आईओटी से जुड़े उत्पाद बनाए जाएंगे।

घोषणा के साथ ही बुक हो जाते हैं मध्यप्रदेश के औद्योगिक पार्क

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य के औद्योगिक पार्कों की सफलता का उल्लेख करते हुए बताया कि धार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मोत्सव 2025 पर 2,000 एकड़ के पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का भूमिपूजन हुआ था और उसी दौरान पार्क का एक-एक प्लॉट बुक हो गया।

इसी प्रकार मोहासा-बाबई में नवकरणीय ऊर्जा उपकरण पार्क पहले, दूसरे और तीसरे चरण पूरी तरह बुक होने के बाद अब चौथे चरण पर कार्य शुरू हो चुका है। पीथमपुर, अवंतिका और विक्रम उद्योगपुरी जैसे क्षेत्रों में भी निवेशकों का भारी विश्वास देखने को मिला है।

ट्रम्प की ईरान को धमकी–समझौता करो वरना तबाह कर देंगे

7 महीने में 10 से ज्यादा धमकियां दीं, हर बार पलटे

न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान को एक बार फिर से तबाह करने की धमकी दी है। मंगलवार को UN में अपने भाषण में उन्होंने कहा- अमेरिका के पास दो रास्ते हैं- ईरान के साथ समझौता करना या उसे खत्म कर देना। अमेरिका-ईरान जंग शुरू होने के बाद से ट्रम्प पिछले 7 महीने में 10 से ज्यादा बार ईरान को तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें पलटकर बातचीत का रास्ता अपनाना पड़ा।

66% अमेरिकी जनता ट्रम्प से नाराज

रॉयटर्स/इप्सोस के सर्वे के मुताबिक, ईरान पर हमला करने से 66% अमेरिकन ट्रम्प से नाराज हैं। सिर्फ 34% लोग ही ट्रम्प के सपोर्ट में हैं। 3 नवंबर को अमेरिका में मिडटर्म इलेक्शन हैं। ट्रम्प नहीं चाहते कि उनकी पार्टी को नुकसान हो। इसी वजह से वो ईरान युद्ध को अब अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं।

ट्रम्प की पार्टी के लोग युद्ध से दूरी बना रहे

मिडटर्म चुनाव से पहले कुछ रिपब्लिकन उम्मीदवार अब ईरान युद्ध जल्द खत्म करने की बात कर रहे हैं। वजह है ईंधन की बढ़ती कीमत और युद्ध को लेकर मतदाताओं की नाराजगी। ऐसे में ट्रम्प की कड़ी चेतावनी अपनी पार्टी के नेताओं और समर्थकों को भी एकजुट रखने का संदेश हो सकती है।

हूती के हमलों से अरब देश परेशान

ईरान के समर्थन वाले हूती लड़ाके लगातार सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। हूती लाल सागर और बाब-अल-मंदेब के आसपास भी एक्टिव हैं। यह रास्ता एशिया और यूरोप के बीच तेल और सामान पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ा तो हूती के हमले और बढ़ सकते हैं। इससे जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ेगा और तेल-सामान महंगा हो सकता है। ट्रम्प नहीं चाहते कि हूती अरब देशों और अमेरिकी सहयोगियों पर हमले बढ़ाएं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प

एक ग्राम ड्रग भी दुनिया से हमारे देश में नहीं आने देंगे न ही यहां से दुनिया में जाएगा

एजेन्सी, नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारा साझा दायित्व और संकल्प होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों को खोखला करने वाली नशे की इस समस्या को हम समाप्त कर दें। हमारा संकल्प हो कि न एक ग्राम ड्रग हम दुनिया से देश में आने देंगे और न ही एक भी ग्राम ड्रग हमारे देश से दुनिया में जाएगी। दुनियभर के युवाओं के कल्याण का संकल्प लेकर हमने यह रोड मैप बनाया है। हमें संवेदना के साथ और इसके महत्व को समझकर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर नशा मुक्त भारत के लिए काम करना होगा।

केन्द्रीय गृह अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने वाले टेलीविजन कमर्शियल का लॉन्च किया। लखनऊ एवं देहरादून में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए जोनल कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एएनटीएफ को सम्मानित भी किया गया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने नए स्वरूप में तैयार एनसीबी की वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। एनसीबी द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ-साथ संबंधित सरकारी विभागों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

शाह ने कहा, देश और दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरा बन चुके नारकोटिक्स पर कड़ा और निर्णायक प्रहार करने और सामूहिक प्रयासों से विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। 31 दिसंबर, 2029 तक हम भारत से नशे के व्यापार को जड़ से उखाड़कर फेंकने में सामूहिक रूप से सफल होंगे। विगत 5 साल में कश्मीर में आतंकवाद, नॉर्थईस्ट में उग्रवाद और नक्सलवाद की समस्या जैसी कई चुनौतियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने सफलता हासिल की है। नशे के खिलाफ यह लड़ाई सभी लड़ाइयों में से सबसे कठिन है, लेकिन हम इस लड़ाई को छोड़ नहीं सकते। इस समस्या के खिलाफ हम सभी को एकजुट होकर जुनून के साथ लड़ना होगा और विजय प्राप्त करनी होगी।

विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 इस लड़ाई में शामिल सभी लोगों के लिए गीता के समान है। यह विजन डॉक्यूमेंट 35 से ज्यादा विभागों के साथ चर्चा के बाद बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लेकर यह कम्प्लीट रोडमैप बनाने का काम किया है, जो निश्चित लक्ष्यों के साथ सबको दिया गया है। इसमें लक्ष्य और समयसीमा भी निश्चित की गई है। कुछ समय बाद इसका रिव्यू भी होगा। नशे के खिलाफ लड़ाई को हमें स्पष्टता के साथ लड़ना है। इस लड़ाई के फोकल पॉइंट्स चिन्हित किया जा चुके हैं और राज्यस्तर पर खुफिया सूचना, जांच, वित्तीय कार्यवाही, अभियोजन को एक ही दिशा में चलाने के लिए एक रोडमैप भी बन चुका हैं। हमने पहली एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस में संस्थागत व्यवस्था बनाई थी और उसे सुदृढ़ किया। दूसरे एएनटीएफ सम्मेलन में उस व्यवस्था को कार्यवाही में बदलने के लिए योग्यता, उसके एक्शन और एग्जीक्यूशन पर चर्चा की। अब यह तीसरा एएनटीएफ सम्मेलन इस रोडमैप को, नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में परिवर्तित करेगा।

अमित शाह ने कहा कि हमने अब तक जो कुछ भी किया है, वह पर्याप्त नहीं है। जब तक हर स्कूल का प्रिंसिपल, गांव का पटवारी, थाने का पीएसआई, राज्य के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव और भारत सरकार के गृह सचिव तक, एक ही दिशा में काम नहीं करते हैं तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज का सम्मेलन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हम टारगेट, टाइमलाइन और अकाउंटबिलिटी तय कर संपूर्ण विजय प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब हमें मीटिंग से मिशन, रिपोर्टिंग से रिज्ल्ट, सीजर से नेटवर्क की समाप्ति और केस से कन्विक्शन तक जाना है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उभरती हुई चुनौतियां, जैसे, सिंथेटिक ड्रग्स और प्रीकर्सर केमिकल्स का डायवर्जन, कम्युनिकेशन की नई तकनीकें, डार्कनेट, ड्रग मार्केट, क्रिप्टो, डेड ड्रॉप डिलीवरी प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के लिए आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले अधिकारियों की एक टीम हर राज्य में बनाई जाए और सफलता को साझा कर इसे पूरे देश में लागू किया जाए।

राज्यसभा की 12 सीटों पर 16 अक्टूबर को वोटिंग

बंगाल-उत्तराखंड में 1-1 और यूपी की 10 सीटें

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव का ऐलान किया। इनमें उत्तर प्रदेश की 10, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल की एक-एक सीट शामिल हैं। 16 अक्टूबर को वोटिंग और काउंटिंग कराई जाएगी। अक्टूबर में होने वाले चुनाव 10 सीटों पर सांसदों के कार्यकाल खत्म होने के बाद हो रहे हैं। जबकि यूपी और बंगाल में एक-एक सीट सांसदों के इस्तीफा देने से खाली हुई है।

यूपी में सांसद दिनेश शर्मा ने 11 सितंबर को इस्तीफा दिया, उन्हें अंडमान और निकोबार का LG बनाया गया है। बंगाल में TMC सांसद कोयल मल्लिक ने इस्तीफा दिया था। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 242 सीटें भरी हुई हैं और 3 खाली हैं। मौजूदा पार्टी स्थिति में BJP के पास 116 सांसद हैं। उत्तर प्रदेश से जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं। इनके अलावा BJP नेता अरुण सिंह, गीता शाक्य, नीरज शेखर, बृजलाल, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है।

सपा नेता राम गोपाल यादव और BSP के इकलौते राज्यसभा सदस्य रामजी गौतम का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। यह सीट सपा के पास जाने की पूरी संभावना है। राज्यसभा में BJP की एक सीट बढ़ने की संभावना है। यह सीट TMC में रहीं कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्हें तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर होने से पहले सदन में भेजा था। जुलाई 2026 में खाली हुई तीन TMC सीटों के उपचुनाव के बाद BJP के 3 नए सदस्य चुने गए, जिससे बंगाल से BJP सांसदों की संख्या 5 हो गई। उत्तराखंड में BJP सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। राज्य में BJP सत्ता में है और विधानसभा में उसके पास बहुमत है। ऐसे में इखढ के पास यह सीट बरकरार रहेगी।

ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं यानी जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं। चुनाव हर दो साल में होते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं। राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं। इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है।

डबरा पुलिस की बड़ी लापरवाही

टीआई-प्रधान आरक्षक की लापरवाही से बन गए 17 फर्जी पासपोर्ट

एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

संदिग्ध बांग्लादेशियों के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाए जाने के मामले में ग्वालियर की डबरा थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। एसटीएफ की जांच में खुलासा हुआ है कि डबरा स्थित बौद्ध बिहार के एक ही पता व एक ही मोबाइल नंबर पर बनाए गए 17 बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट आवेदनों का सत्यापन 2021-22 में बिना जमीनी जांच किए ही 'ओके' कर दिए गए थे। यही कारण है कि फर्जी पासपोर्ट कांड में अब डबरा पुलिस के तत्कालीन पुलिस कर्मियों पर तलवार लटक गई है।

एसटीएफ डीआईजी राहुल लोढ़ा के अनुसार, सत्यापन में घोर लापरवाही बरतने पर डबरा के तत्कालीन थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और वैरीफिकेशन सेल इंचार्ज प्रधान आरक्षक भूपेंद्र गुर्जर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए एसएसपी ग्वालियर को पत्र लिखा है। इसके अलावा पासपोर्ट सेल प्रभारी और प्रक्रिया से जुड़े अन्य पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। भोपाल से गिरफ्तार फर्जी पासपोर्ट एजेंट नसीम अख्तर से पूछताछ के आधार पर जांच अब पासपोर्ट सेवा केंद्र तक

पहुंच गई है। एसटीएफ ने उस पासपोर्ट अधिकारी की जानकारी जुटा ली है, जिससे नसीम की कथित सांठगांठ थी। इसके साथ ही नसीम का एक अन्य साथी भी रडार पर है। फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले संदिग्धों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ की टीमें दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और असम में लगातार छापेमारी और पड़ताल कर रही हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान डबरा थाने के पासपोर्ट सेल का प्रभार हवलदार भूपेंद्र गुर्जर के पास था। नियमानुसार आवेदकों के दिए गए पते और दस्तावेजों की मौके पर जाकर भौतिक जांच करने की जिम्मेदारी पासपोर्ट सेल की होती है। लेकिन जांच में सामने आया कि अधिकारियों और कर्मचारियों ने मौके पर जाए बिना ही फर्जी दस्तावेजों की रिपोर्ट ओके कर दी।

1991 की एफआईआर छिपाने का आरोप

दतिया विधायक घनश्याम सिंह की सदस्यता को हाईकोर्ट में चुनौती, भाजपा नेता ने लगाई याचिका

एक सत बुलेटिन, जबलपुर

दतिया उपचुनाव के बाद एक बार फिर विधानसभा सीट चर्चा में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के खिलाफ चुनावी शपथ पत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने अधिवक्ता शिवम गौतम के माध्यम से 17 सितंबर को दायर की है।

याचिका में दावा किया गया है कि घनश्याम सिंह ने उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में दो आपराधिक मामलों की जानकारी दी, लेकिन 1991 में दर्ज एक अन्य FIR का उल्लेख नहीं किया। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए चक्काजाम से जुड़ा बताया गया है। याचिका के मुताबिक उस दौरान करीब 22 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उनमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था। घनश्याम सिंह ने 30 जुलाई को हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हराया था। उन्हें 66,757 और तिवारी को 60,741 वोट मिले थे।

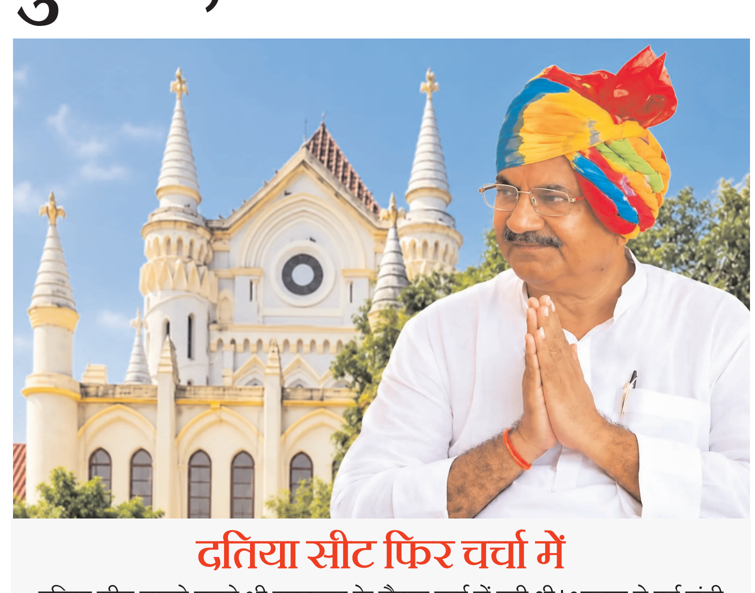

दतिया सीट फिर चर्चा में

दतिया सीट इससे पहले भी उपचुनाव के दौरान चर्चा में रही थी। भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया। उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया। अब घनश्याम सिंह के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने से यह सीट फिर सुर्खियों में है। याचिका में चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है।

सदस्यता पर क्या असर होगा?

फिलहाल घनश्याम सिंह दतिया से विधायक हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में शपथपत्र में कथित तौर पर जानकारी छिपाने के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई और अदालत के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों का कानूनी आधार क्या है और इसका उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई असर पड़ता है या नहीं। मौजूदा स्थिति में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दतिया सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा। दतिया में इससे पहले 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। भारती की सदस्यता दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद गई थी।

मंत्री भूरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिए जनभागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर गूंजेगा 'सेवा, पोषण और सम्मान' का संकल्प

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

मध्यप्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल शासकीय सेवाओं के वितरण स्थल के रूप में नहीं, बल्कि सेवा, पोषण, सीखने, सहभागिता और सम्मान के जीवंत केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी 'आंगन मिलन सेवा' अभियान आयोजित किया जाएगा। अभियान के अंतर्गत 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी 97,882 आंगनवाड़ी केंद्रों पर तीन दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मंगलवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अधिकारियों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हर आंगनवाड़ी बने सेवा, पोषण और सम्मान का केंद्र मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि 'आंगन मिलन सेवा' को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे समुदाय और आंगनवाड़ी के बीच मजबूत जुड़ाव का माध्यम बनाया जाए। अभियान का मूल उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों, माताओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा अन्य हितग्राहियों तक पोषण, स्वास्थ्य और कल्याण सेवाओं की नियमित एवं प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए, जिसमें सेवा के साथ सम्मान और जनभागीदारी भी दिखाई दे। माताओं-बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और संवाद पर विशेष फोकस अभियान के प्रथम दिवस बाल स्वास्थ्य और आनंदमयी गतिविधियों पर विशेष जोर रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की गतिविधियां, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संदेशों का वाचन तथा डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ता का सम्मान भी

किया जाएगा। इसके साथ ही 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की माताओं, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा महिला हितग्राहियों से संवाद होगा। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गर्भावस्था एवं प्रसवोत्तर देखभाल, संतुलित आहार, एनीमिया, स्तनपान और शिशु देखभाल जैसे विषयों पर पोषण संवाद आयोजित होंगे। बच्चों को फल एवं मिठाई का वितरण भी किया जाएगा। 'मेरी कहानी, मेरी सफलता' बताएगी योजनाओं के प्रभाव की कहानी अभियान के द्वितीय दिवस को 'मेरी कहानी, मेरी सफलता' की थीम पर लाभार्थी संवाद आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं और परिवारों के अनुभव सामने लाए जाएंगे। लाभार्थी माताओं को अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों को साझा करने का अवसर दिया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, टेक होम राशन, गर्म पका भोजन, पोषण सेवाओं सहित महिला एवं बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरल एवं बोलचाल की भाषा में दी जाएगी। जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित कर उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधिगण कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और आंगनवाड़ी केंद्रों पर आयोजित गतिविधियों की शोभा बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों, विभागीय अमले और समुदाय की सहभागिता से अभियान को व्यापक जन-अभियान का स्वरूप दिया जाए।

एलिवेटेड कॉरीडोर पर रैन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अभी से करें इंतजाम

बैरागढ़ एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण मार्च 2027 तक हर हाल में पूर्ण करें : लोक निर्माण मंत्री

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल**

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने मंगलवार को विधायक श्री रामेश्वर शर्मा के साथ बैरागढ़ में निर्माणाधीन एलिवेटेड ब्रिज का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे निर्माणाधीन मार्ग का भ्रमण कर कार्य की भौतिक प्रगति, गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था, सर्विस रोड, तथा नागरिकों के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री श्री सिंह ने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति और कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि निर्माण के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करना विभाग तथा निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मंत्री श्री सिंह ने सभी कमियों और अव्यवस्थाओं को 3 दिवस के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में बरती गई लापरवाही और विलंब के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार पेनाल्टी लगाने को कहा। साथ ही बंद अथवा अव्यवस्थित स्ट्रीट

लाइटों को चालू करने और निर्माण स्थल पर सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने सर्विस रोड की खराब स्थिति को देखकर इसे शीघ्र दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य ब्रिज का निर्माण पूरा होने तक सर्विस रोड ही नागरिकों के आवागमन का प्रमुख माध्यम है, इसलिए इसे सुरक्षित और सुगम बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सिविल अस्पताल के आसपास की अव्यवस्थाओं को तत्काल सुधारने तथा मरीजों, एम्बुलेंस और आम नागरिकों के निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों एवं निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब ब्रिज का संपूर्ण निर्माण कार्य मार्च 2027 तक हर हाल में पूर्ण किया जाए। इस समय-सीमा में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य की माइक्रो प्लानिंग करने की भी निर्देश दिए जिसमें पर्ट चार्ट के आधार पर एक्टिविटी प्लान बनाने और इसके आधार पर साप्ताहिक प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य अभियंता निर्माण कार्य की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करेंगे। कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन प्रत्येक 15 दिवस में मंत्री को प्रस्तुत किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि संत हिरदाराम नगर का यह मुख्य मार्ग अत्यधिक यातायात घनत्व वाला क्षेत्र है। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही से गंभीर दुर्घटना की संभावना हो सकती है। उन्होंने निर्माण एजेंसी को सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मंत्री श्री सिंह ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान यातायात को निर्बाध बनाए रखने के लिए केवल उसी स्थान पर सेफ्टी बैरियर लगाए जाएं, जहां वास्तविक रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। जिन स्थानों पर निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, वहां से अनावश्यक बैरियर तत्काल हटाए जाएं, ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित हो सके। उन्होंने निर्माण स्थल से मलबा एवं अन्य अपशिष्ट निर्माण सामग्री तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के कारण स्थानीय व्यापारियों एवं रहवासियों को होने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए।

जबेरा-तेंदूखेड़ा क्षेत्र के 5 प्राचीन स्थल राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल मंत्री लोधी

■ एक सत बुलेटिन, **दमोह।**

जबेरा से विधायक एवं मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि जबेरा-तेंदूखेड़ा क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग द्वारा क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण प्राचीन एवं ऐतिहासिक धरोहरों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मढ़ा मंदिर, ग्राम दौनी, तहसील तेंदूखेड़ा,सूर्य मंदिर, ग्राम मोहड़, तहसील तेंदूखेड़ा,मढ़ा मंदिर, ग्राम बड़दुंवा, तहसील जबेरा,श्री राम-जानकी मंदिर, ग्राम पुंवार, तहसील जबेरा, वंशीपुर मठ, जबेरा राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए गए हैं। मंत्री श्री लोधी ने कहा कि इन प्राचीन स्थलों को राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किए जाने से इनके समुचित संरक्षण, संवर्धन एवं ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। दमोह जिला सदियों पुरानी सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपराओं का केंद्र रहा है। इन धरोहरों का संरक्षण आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। क्षेत्रवासियों ने भी इस महत्वपूर्ण पहल पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

अलसुबह दी दबिश, 14200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद, 12 भट्टियां नष्ट, 2 बॉयलर और 71 ड्रम जब्त

■ एक सत बुलेटिन, **बैरसिया।**

अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय के खिलाफ भोपाल देहात पुलिस एवं आबकारी विभाग ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए तरावली डेरे में अलसुबह दबिश दी। कार्रवाई के दौरान अलग-अलग डेरों में बने एवं खाली पड़े मकानों की तलाशी लेकर करीब 14,200 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। मौके से 71 ड्रम, 12 अवैध शराब की भट्टियां तथा 2 बॉयलर भी बरामद किए गए। शेष अवैध शराब को नियमानुसार मौके पर ही नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सोनकर,एसडीओपी बैरसिया सुश्री वैशाली कराहलिया एवं सहायक

जिला आबकारी अधिकारी वर्षा उइके के नेतृत्व में यह संयुक्त कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, 21 सितंबर 2026 को मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने तरावली डेरे में अलसुबह दबिश दी। कार्रवाई की भनक लगते ही मौके पर मौजूद कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद टीम ने अलग-अलग डेरों में खुले एवं खाली पड़े मकानों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महुआ शराब से भरे 71 ड्रमों में करीब 14,200 लीटर अवैध महुआ शराब मिली। कार्रवाई के दौरान आवश्यक मात्रा को जब्त कर शेष अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जमीन के अंदर अवैध रूप से महुआ शराब तैयार करने के लिए बनाई गई 12 भट्टियां भी मिलीं, जिन्हें नष्ट किया गया। शराब निर्माण में प्रयुक्त 2 बॉयलर जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली अन्य सामग्री के संबंध में भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

राज्यमंत्री गौर ने अवधपुरी में किया सड़कों का निरीक्षण

गड्ढे तत्काल भरने और स्ट्रीट लाइटें चालू करने के दिए निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के अवधपुरी स्थित आदर्श विहार, रीगल टाउन, सरला स्टेट, न्यू फोर्ट कॉलोनी एवं कंचन नगर में सड़कों की स्थिति तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्गों की जर्जर स्थिति, स्थान-स्थान पर उभरे गड्ढों एवं खुले सीवेज नेटवर्क को देखकर राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्यपालक एजेंसियों एवं ठेकेदारों की शिथिलता पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण करने के कड़े निर्देश

दिए। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि निर्माण एजेंसियों एवं ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतने दिया जाएगा। आगामी पर्वों एवं त्योहारों के दृष्टिगत नागरिकों को सुगम, सुरक्षित एवं बाधारहित आवागमन उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उन्होंने वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों के गड्ढों का भराव कार्य तत्काल एवं पूर्ण मजबूती के साथ कराने के निर्देश दिए। साथ ही राजस्व एवं नगर निगम दल को सीमांकन कर सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण अविलंब हटाने तथा आवश्यकतानुसार मार्ग चौड़ीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि दिन के समय आमजन की आवाजाही एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य मुख्य रूप से रात्रिकालीन समय में निष्पादित किए जाएं। क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने के संबंध में राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने बंद पड़ी समस्त स्ट्रीट लाइटों को आगामी 10 दिवस की निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने रहवासी क्षेत्र में नियमों के विपरीत संचालित गोदाम को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर सीलिंग की कठोर कार्यवाही करने के भी आदेश दिए। रहवासियों से संवाद करते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि मानसून पश्चात क्षतिग्रस्त मार्गों के स्थाई एवं गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाएगा।

भोपाल मंडल के कोचिंग डिपो एवं रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता और निरीक्षण गतिविधियां आयोजित

स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में गतिविधियां

■ एक सत बुलेटिन, **भोपाल।**

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत भोपाल मंडल में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज विभिन्न रेलवे स्टेशनों एवं कोचिंग डिपो में विशेष गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के दौरान रेल परिसरों, ट्रेनों एवं यात्री सुविधाओं में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अभियान के अंतर्गत यांत्रिक विभाग द्वारा भोपाल मंडल के सभी कोचिंग डिपो में प्राथमिक ट्रेनों की स्वच्छता व्यवस्था का व्यापक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान, सफाई मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), शौचालयों, कोच के अंदर एवं बाहरी हिस्सों की सफाई, लिनेन तथा पेंट्री की स्वच्छता की जांच की गई। सफाई कार्य

में उपयोग होने वाली मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता की भी जांच की गई तथा आवश्यकतानुसार सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत बीना रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय विद्यालय, बीना के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों ने अपने प्रभावी अभिनय एवं संदेश के माध्यम से यात्रियों को रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में स्वच्छता बनाए रखने तथा कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के लिए जागरूक किया।

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और 'स्वच्छ रेल-स्वच्छ परिसर' के संकल्प में सहभागी बनने का संदेश दिया गया।

यात्रियों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की। भोपाल स्टेशन के यार्ड में सफाई कार्य में उपयोग की जा रही विभिन्न मशीनों एवं उपकरणों की कार्यशीलता की जांच की गई तथा मशीनों से संबंधित सफाई कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि स्वच्छता कार्य में उपयोग होने वाले उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं तथा आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध हैं। भोपाल मंडल द्वारा 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के माध्यम से स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ स्टेशन और स्वच्छ रेल परिसर के उद्देश्य को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

1991 के केस की जानकारी नहीं देने का आरोप

उपचुनाव जीतने के बाद घनश्याम सिंह की विधायकी को चुनौती, कोर्ट पहुंचा मामला

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

दतिया उपचुनाव के बाद एक बार फिर विधानसभा सीट चर्चा में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के खिलाफ चुनावी शपथ पत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी कथित तौर पर छिपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता दीपक बेलपत्री ने अधिवक्ता शिवम गौतम के माध्यम से 17 सितंबर को दायर की है।याचिका में दावा किया गया है कि घनश्याम सिंह ने उपचुनाव के दौरान दाखिल शपथ पत्र में दो आपराधिक मामलों की जानकारी दी, लेकिन 1991 में दर्ज एक अन्य स्त्रढ्ढक्र का उल्लेख नहीं किया। यह मामला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए चक्काजाम से जुड़ा बताया गया है। याचिका के मुताबिक उस दौरान करीब 22 लोगों के खिलाफ स्त्रढ्ढक्रदर्ज हुई थी और उनमें घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था। घनश्याम सिंह ने 30 जुलाई को हुए दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हराया था। उन्हें 66,757 और तिवारी को 60,741 वोट मिले थे फिलहाल घनश्याम सिंह दतिया से विधायक हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में शपथपत्र में कथित तौर पर जानकारी छिपाने के आधार पर उनके निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका पर सुनवाई और अदालत के फैसले के बाद ही यह तय होगा कि आरोपों का कानूनी आधार क्या है और इसका उनकी विधानसभा सदस्यता पर कोई असर पड़ता है या नहीं। मौजूदा स्थिति में यह कहना जल्दबाजी होगी कि दतिया सीट पर दोबारा उपचुनाव होगा। दतिया में इससे पहले 30 जुलाई को उपचुनाव हुआ था। यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। भारती की सदस्यता दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद गई थी। दतिया सीट इससे पहले भी उपचुनाव के दौरान चर्चा में रही थी। भाजपा ने पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया।

उपचुनाव में घनश्याम सिंह ने आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराया। अब घनश्याम सिंह के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दिए जाने से यह सीट फिर सुर्खियों में है। याचिका में चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है।

छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट:

अवमानना याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने किया तलब, आईजी को तमीली के निर्देश, विभाग ने नहीं किया आदेश का पालन

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जबलपुर रेंज के आईजी को वारंट तामील कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही एसपी को 1 अक्टूबर 2026 को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। मामला एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के निधन के बाद विभाग द्वारा की गई रिकवरी से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाईकोर्ट के रिकवरी पर रोक लगाने और राशि लौटाने के आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं किया गया।

पति की मौत के बाद 2.24 लाख रुपए की रिकवरी

जबलपुर निवासी सीता तिवारी ने अधिवक्ता सचिन पांडे के माध्यम से अवमानना याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार उनके पति संतोष तिवारी छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग में पदस्थ थे। सेवाकाल के दौरान 14 अगस्त 2020 को उनका निधन हो गया। इसके बाद विभाग ने उनके खिलाफ 2.24 लाख रुपए की रिकवरी निकाल दी। मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की कोर्ट में हुई थी। कोर्ट ने रिकवरी का आदेश निरस्त करते हुए राशि 8 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया था। 2025 में जारी हुआ था अवमानना नोटिस सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2025 में अवमानना नोटिस जारी होने के बाद भी आदेश के पालन की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। नोटिस मिलने और आवश्यक मंजूरी के संबंध में जानकारी दी थी, लेकिन इसके बाद भी आदेश के पालन की कार्रवाई नहीं हुई। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म व मारपीट के आरोपी को नहीं मिली जमानत

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

जबलपुर जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने विवाह का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म और मारपीट करने के मामले में आरोपी बनाए गए जबलपुर निवासी आकाश काछी को राहत देने से इंकार करते हुए आरोपित का नियमित जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार अधारताल थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपित ने पीड़िता को विवाह का झांसा देकर अपने साथ ले गया और सुहागी व हरियाणा में रखकर उसका शारीरिक शोषण व मारपीट की। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 व 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया। मामलें में जमानत का लाभ लेने आरोपित की ओर से जमानत आवेदन अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय वर्मा व पीड़िता की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने अपराध की गंभीरता, विवेचना लंबित होने व पीड़िता और उसके स्वजनों को प्रभावित किए जाने की आशंका बताई। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपित के पूर्व विवाह संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि दस्तावेजों की प्रामाणिकता और उनका प्रभाव विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर तय होगा। प्रकरण की परिस्थितियों और साक्षियों को प्रभावित किए जाने की आशंका को देखते हुए अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

केएफडब्ल्यू (जर्मनी) फंडेड परियोजना के अंतर्गत

पूर्व क्षेत्र कंपनी में पीएम कुसुम एवं नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

केएफडब्ल्यू (जर्मनी) द्वारा फंडेड Accompanying Measures Project के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के अधिकारियों एवं अभियंताओं के लिए पीएम कुसुम, सोलर थर्मल एवं नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एकीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम होटल सत्यम अशोका, जबलपुर में संपन्न हुआ । कार्यक्रम का आयोजन मर्काडोस एनर्जी मार्केट्स इंडिया के प्रैक्टिस हेड एवं सीओओ श्री रमनदीप सिंह, पार्टनर श्री मोहित भारद्वाज एवं निदेशक श्री सिद्धार्थ घोष के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण में पूर्व क्षेत्र कंपनी के कार्यपालन अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं ने सहभागिता की । प्रशिक्षण के दौरान पीएम कुसुम योजना, सोलर थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा बिलिंग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विद्युत ग्रिड में एकीकरण से संबंधित तकनीकी एवं परिचालन पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान पूर्व क्षेत्र कंपनी के मैदानी अमले के समक्ष आने वाली विभिन्न व्यावहारिक चुनौतियों एवं उनके समाधान पर विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया । प्रशिक्षण के दौरान पूर्व क्षेत्र कंपनी में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, संचालन, बिलिंग एवं ग्रिड एकीकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवादात्मक चर्चा हुई। उपस्थित अभियंताओं ने तकनीकी एवं परिचालन संबंधी प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा समाधान किया गया। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग एवं विद्युत वितरण व्यवस्था में इसके बेहतर एकीकरण से संबंधित व्यावहारिक अनुभव भी साझा किए गए ।

एमबीबीएस छात्र को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करें- हाईकोर्ट

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्तपीठ ने महावीर मेडिकल कालेज, भोपाल के एमबीबीएस छात्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आवेदक छात्र को एक अक्टूबर 2026 से शुरू हो रही थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम आदेश दिया है। इसके साथ ही संयुक्तपीठ ने मामले में राज्य शासन, संचालक मेडिकल एजुकेशन और संबंधित मेडिकल कालेज को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर निवासी छात्र विश्वास बाजपेयी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आवेदक के अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि छात्र का प्रवेश मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत हुआ था। उक्त योजना के तहत राज्य सरकार ने प्रथम वर्ष की 8.33 लाख रुपये फीस जमा की थी। छात्र प्रथम सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो गया था। योजना के प्रावधान के अनुसार परीक्षा में असफल होने पर विद्यार्थी योजना से बाहर हो जाता है। अधिवक्ता ने बताया कि छात्र ने बाद में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और अब थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुका है। योजना से बाहर होने के कारण उसकी फीस जमा नहीं हुई और इसी वजह से कालेज ने उसे आगामी परीक्षा में शामिल किए जाने को लेकर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने छात्र को थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा में बैठाने का आदेश दिया। साथ ही अनावेदकों से जवाब तलब किया है।

यूक्रेन युद्ध में छूटी पढ़ाई, अब हाईकोर्ट से आसः छात्र की याचिका पर कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य को अंतिम अवसर

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेन से भारत लौटे भोपाल के एक मेडिकल छात्र की एमबीबीएस की अधूरी पढ़ाई पूरी कराने से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कड़ा जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर 2026 के लिए निर्धारित की है। भोपाल के कोटरा सुल्तानाबाद निवासी छात्र अनूप पचौरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2021 में नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यूक्रेन की हॉरबाचेव्स्की टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था। उन्हें 14 जून 2021 को आमंत्रण मिला और 11 अक्टूबर 2021 को वीजा जारी होने के बाद, उन्होंने 3 नवंबर 2021 को फीस जमा कर 7 नवंबर से यूक्रेन में पढ़ाई शुरू कर दी थी। याचिका में बताया गया है कि जब उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही थी, तभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसके चलते उन्हें मजबूरी में भारत लौटना पड़ा। भारत आने के बाद उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की, लेकिन स्थितियां जटिल होती गईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि वह न तो अपनी मेडिकल शिक्षा किसी अन्य देश में स्थानांतरित करवा पा रहा है और न ही भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का कोई स्पष्ट मार्ग मिल पा रहा है।

टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत मामले में केंद्र और एनटीसीए से जवाब - तलब

वैक्सीनेशन और रिक्त पदों की जानकारी व 10 साल में बाघ संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश को मिली राशि का ब्योरा पेश करने के निर्देश

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायाधीश बीपी शर्मा की संयुक्तपीठ ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में केंद्र सरकार और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी (एनटीसीए) से जवाब तलब किया है। संयुक्तपीठ ने टाइगर रिजर्व में बाघों को संक्रमण से बचाने के लिए किए जा रहे वैक्सीनेशन, वन्यजीव चिकित्सा व्यवस्था तथा रिक्त पदों की स्थिति की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी बताने को कहा है कि पिछले 10 वर्षों में मध्यप्रदेश में बाघ संरक्षण के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई। एनटीसीए को भी प्रदेश के टाइगर रिजर्व के लिए जारी राशि का वर्षवार ब्योरा प्रस्तुत करना है। न्यायालय ने मामले में इससे पहले 19 अगस्त की सुनवाई में एनटीसीए को दस वर्ष का फंड संबंधी डाटा पेश करने के निर्देश दिए थे। प्रकरण पर सुनवाई के दौरान टाइगर रिजर्व में संक्रमण की रोकथाम का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस दौरान विशेषकर कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (सीडीवी) की आशंका के बीच बाघों की मौत के बाद कुत्तों के वैक्सीनेशन और रोग निगरानी को महत्वपूर्ण माना गया। एनटीसीए ने भी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास कुत्तों के नियमित टीकाकरण तथा वन्यजीवों की स्वास्थ्य निगरानी मजबूत करने की सलाह दी है। एकलपीठ ने प्रदेश के टाइगर रिजर्व में वन्यजीव पशु चिकित्सकों समेत आवश्यक पदों की स्थिति और उन्हें भरने के संबंध में भी जवाब मांगा है। याचिका में बाघों की मौत रोकने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, रोग नियंत्रण और एनटीसीए के निर्धारित प्रोटोकाल के पालन का मुद्दा उठाया गया है। गौरतलब हो कि कान्हा टाइगर रिजर्व में अप्रैल-मई 2026 के दौरान लगातार कई बाघों की मौत के बाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई।

2011 में सवा पांच किलो से हुई थी शुरुआत, अब वजन हुआ 41 किलो

गणेश उत्सव विशेष-पुलिस के पहरे में विराजित बप्पा, 41 किलो चांदी से हुआ अलंकृत

■ एक सत बुलेटिन, जबलपुर

पुलिस के कड़े पहरे के बीच जबलपुर में स्थापित 41 किलोग्राम शुद्ध चांदी से बनी गणेश जी की प्रतिमा इस बार गणेश उत्सव का मुख्य आकर्षण बनी हुई है। ग्वारीघाट के ललपुर रोड स्थित श्री सिद्ध गणेश धाम में स्थापित इस भव्य प्रतिमा की अनोखी परंपरा और शहर के अन्य पंडालों में चल रहे विशेष आयोजनों ने उत्सव के उल्लास को और बढ़ा दिया है। 2011 में सवा पांच किलो से हुई थी शुरुआत, अब वजन हुआ 41 किलो ग्वारीघाट के ललपुर रोड स्थित श्री सिद्ध गणेश धाम के संस्थापक महंत स्वामी प्रमोद महाराज के अनुसार, वर्ष 2011 में सवा पांच किलो चांदी से इस मूर्ति की स्थापना की गई थी। मान्यता है कि भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने पर वे चांदी दान करते हैं, जिससे हर साल बप्पा की प्रतिमा का स्वरूप और वजन बढ़ाया जाता है। वर्तमान में इस दिव्य प्रतिमा का कुल वजन 41 किलो 100 ग्राम शुद्ध चांदी हो चुका है। मंदिर में अब तक हजारों मनोकामना अर्जियां भी लग चुकी हैं। अल्पाइन और बहुमूल्य चांदी की इस विशाल प्रतिमा की सुरक्षा के लिए ग्वारीघाट थाने से चार पुलिसकर्मी

चौबीस घंटे तैनात रहते हैं, साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी पैनी नजर रखी जाती है। उत्सव के दौरान 14 तारीख से लगातार सहस्त्रार्चन, अथर्वशीर्ष पाठ से महाभिषेक, मंगला आरती और महाआरती का आयोजन हो रहा है। अनंत चतुर्दशी या विसर्जन के दिन पूजा-विधि के बाद प्रतिमा को कुंड में आवाहन मुक्त कर पुनः गर्भगृह में सुरक्षित रख दिया जाता है।शिव स्वरूप में बप्पा और अनोखी परंपराएं शहर के अन्य हिस्सों में भी गणेश उत्सव की पुरानी और अनूठी परंपराएं देखने को मिल रही हैं: शिव स्वरूप बप्पाः एकदंत गणेश उत्सव समिति ने बप्पा को शिव स्वरूप में स्थापित किया है, जिनकी सूंड में माता महाकाली विराजमान हैं। यहां 23 तारीख को महाआरती और 24 को हवन-भंडारे का अनुष्ठान होगा। सदर के 60 साल पुराने पावन आयोजनः सदर के आजाद चौक में दुर्गा और गणेश सेवा मंडल पिछले 60 वर्षों से सामूहिक सहभागिता से उत्सव मना रहा है। वहीं, सदर की गली नंबर 11 में श्री शिव गणेश उत्सव समिति 38 सालों से बप्पा की स्थापना कर रही है, जहां के अधिकांश लोग फुटबॉल खेल से जुड़े हैं। महानद्दा के 'राजा' और मावली फेटाः महानद्दा तालाब के पास मां नर्मदा गणेश उत्सव समिति द्वारा पिछले 13 सालों से विराजा जा रहे बप्पा को पारंपरिक मावली फेटा (पगड़ी) पहनाया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे की याद दिलाता है।

संपादकीय

जो आयोग चाहे, वो वोटर

करीब 98 वर्षीय लालकृष्ण आडवाणी देश के उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री रहे हैं। वह नई दिल्ली से लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। उन्हें, बेटी प्रतिभा और बहू को मतदाता सूची में शामिल करने पर सवाल हैं, लिहाजा उन्हें चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। देश के मौजूदा विदेश मंत्री एस. जयशंकर, उनकी जापानी पत्नी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी को भी नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के मतदाता होने पर भी चुनाव आयोग को संदेह है। बहरहाल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का मामला किसी तरह निपटा लिया गया है, लेकिन केजरीवाल, उनके 85 वर्षीय माता-पिता, उनकी आईआरएस रहीं और सरकारी पेंशनधारी पत्नी और बेटे के दिल्ली में मतदाता होने पर आयोग के सवाल हैं, लिहाजा उन्हें नोटिस के जवाब देने ही पड़ेंगे। देश के कानून मंत्री रहे, चांदनी चौक के पूर्व सांसद, मौजूदा राज्यसभा सांसद एवं सर्वोच्च अदालत के प्रख्यात अधिवक्ता कपिल सिब्बल के मतदाता होने पर आयोग को क्या आपत्तियां हैं, कमोबेश हमारी समझ के बाहर है। यहां तक कि मौजूदा चुनाव आयुक्त एसएस संधू, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता के समकक्ष ही हैं, को भी नोटिस भेजा गया है कि उनके नाम की स्पेलिंग (वर्तनी) 2002 के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती, लिहाजा वह स्पष्ट करें। बेहद हास्यास्पद है कि सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद, थलसेना प्रमुख रहे जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रहीं जस्टिस रंजना देसाई, सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला आदि अति विशिष्ट चेहरों को भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजे हैं, तो आम मतदाता की कराहें, चीखें, गुहार कौन सुनेगा? कैग प्रमुख के. संजय मूर्ति के माता-पिता के नाम भी नहीं हैं। बेशक चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हमारा पक्का यकीन है कि अंततः इन सभी नामों को दिल्ली की मतदाता-सूची में जोड़ा जाएगा। क्या चुनाव आयोग अपनी नालायकी पर माफी मांगेगा?

दरअसल हमारा बुनियादी और गंभीर सवाल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के प्रारूप पर है। यह अभियान चलाने वाले अधिकारियों की मेधा, सामान्य बुद्धि, पर भी तरस आता है। ज्ञानेश कुमार भी सामूहिक तौर पर खलनायक हैं। क्या संविधान के अनुच्छेद 324 और 325 में चुनाव आयोग को यही विशेष शक्तियां दी गई हैं कि मतदाता वही होगा, जिसे चुनाव आयोग चाहेगा? लेकिन अनुच्छेद 326 में यह प्रावधान भी है कि देश का प्रत्येक 18 वर्षीय वयस्क नागरिक अधिकृत मतदाता होगा। यह मताधिकार क्यों छीना जा रहा है? एसआईआर के तहत करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम अभी तक काटे जा चुके हैं। उनके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। लोग दिवंगत भी हुए होंगे, तो नए मतदाता भी जुड़े होंगे! मताधिकार गंवाने वालों की यह कोई सामान्य संख्या नहीं है और एसआईआर अभी जारी है। यह सवाल लगातार अनुत्तरित क्यों है कि आयोग काटे गए नामों का खुलासा, वर्गीकरण समेत, सर्वोच्च अदालत को दे और वहां से देश को अवगत कराया जाए। ज्ञानेश कुमार गुप्ता संविधान के भी सुप्रीम नहीं हैं। संविधान के तहत ही उन्हें इस पद का दायित्व और विशेषाधिकार दिए गए हैं। दरअसल हमने जिन अति विशिष्ट चेहरों का उल्लेख किया है, उन्हें निर्वाचित भी घोषित किया जा चुका है और यह काम आयोग ने ही किया और ये लोग दशकों से मतदाता भी रहे हैं।

आडवाणी और केजरीवाल के माता-पिता की जो उम्र है, उसके मुताबिक वे 60-70 साल से मतदान कर रहे होंगे, अचानक उस पर सवाल किए जा रहे हैं! क्या अब मतदाता की परिभाषा बदल गई है और वे 2002 की मतदाता-सूची के आधार पर ही तय किए जाएंगे? यह कोई ब्रह्म-ग्रंथ है क्या? यह पुनरीक्षण उसी आधार पर किया जाना चाहिए, जो मतदाता ने फॉर्म भरा है। मतदाता ही अपने बारे में ब्यौरा देने को स्वतंत्र और अधिकृत है। 2002 में कोई गलती रह गई होगी, तो उसके आधार पर आप किसी का मताधिकार छीन लेंगे? माता-पिता का नाम देने की स्वतंत्रता भी मतदाता की होनी चाहिए और उनका मिलान करना ही गलत है।

पहाड़ सब सह लेगा यह भ्रम तोड़ना होगा

कुमार रोहित

> 20 सितंबर का विश्व क्लीनअप दिवस पहाड़ों में बढ़ते कचरे की चुनौती की याद दिलाता है, जबकि 27 सितंबर का विश्व पर्यटन दिवस उस अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान खींचता है, जिसकी हिमाचल में बड़ी भूमिका है। सवाल यह है कि पर्यटन बढ़े, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ को न चुकानी पड़े। हिमाचल की रीढ़ कहे जाने वाला पर्यटन ही यहां लाखों लोगों के रोजगार और कमाई का मुख्य सहारा है।

पर्यटन स्थलों का प्लास्टिक और कचरा नदियों, खड्डों और खेतों तक पहुंचता है। इसलिए सडक, होटल और पर्यटकों की संख्या तय करते समय कचरा प्रबंधन की क्षमता भी देखनी होगी। जरूरी है कि जलस्त्रोतों पर कब्जा रोका जाए, संवेदनशील ढलानों की पहचान हो, मलबा फेंकने के नियम सख्ती से लागू हों और नदी-खड्डों का प्राकृतिक दायरा सुरक्षित रखा जाए। पंचायतों और स्थानीय समुदायों को निगरानी में असली भूमिका मिले, क्योंकि पहाड़ की नब्ज वही बेहतर समझता है जो पीढ़ियों से उसके साथ जी रहा है

पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर जब हिमाचल के पहाड़ों, जंगलों और नदियों की चिंता सामने रखी थी, तब सवाल पर्यावरण बचाने का था। मानसून बीतते-बीतते वही सवाल और सख्त हो गया है- क्या पहाड़ों को बचाए बिना हम विकास की रफ्तार बनाए रख सकते हैं? इस साल की आपदाओं ने एक कड़वा सच फिर उजागर किया है- पहाड़ों पर बारिश पहले भी होती थी, पर हर भारी बारिश तबाही नहीं बनती थी। तेज बारिश और बदलता मौसम जोखिम बढ़ाते हैं, लेकिन वही जोखिम आपदा का रूप लेगा या नहीं, यह ढलानों की स्थिति, भूमि-उपयोग और हमारी तैयारी पर भी निर्भर करता है। ढलानों की अंधाधुंध कटाई, हरियाली का कम होना, बेतरतीब निर्माण, नदी-खड्डों के रास्ते रोकना और खराब जल निकासी- जोखिम को आपदा में बदलने के लिए इतना काफी है। इसलिए संकट सिर्फ बारिश का नहीं, हमारी तैयारी और विकास के तौर-तरीकों का भी है। वर्ष 2026 के मानसून में हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। 12 सितंबर को उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं से करीब 1684 करोड़ रुपए का नुकसान और 120 लोगों की मौत हो चुकी थी। पिछले सालों की आपदाएं भी यही बताती हैं कि नुकसान सिर्फ मौसम से नहीं बढ़ता।

खतरे वाली जगहों पर बस्तियां बढ़ना और हमारी तैयारियों की कमी भी नुकसान को बड़ा करती है। लाहौल के कड़ू नाला में पहाड़ी दरकने से 13 यात्रियों की जान गई, तो कई जगह खड्डों-नालों के उफान ने घरों और सडकों को तोड़ दिया। सडकें विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन पहाड़ काटते समय ढलान की मजबूती, पानी की निकासी और मलबे को ठिकाने लगाने की बात भूल जाएं तो कीमत भारी पड़ती है। कटान का मलबा जब खड्डों और नदियों में गिरता है, तो उनका बहाव और तल दोनों बिगड़ते हैं। परवाणू से कैथलीघाट तक फोरलेन के लिए काटी गई पहाडि ?ों का मलबा कौशल्या खड्ड को प्रभावित कर रहा है। बरसात में मलबे और तेज बहाव की यह स्थिति आसपास की सडकों और बस्तियों के लिए जोखिम बढ़ाती है। जलविद्युत और दूसरी परियोजनाओं में भी पहाड़ के भूगोल और सुरक्षा को पहले रखना होगा। बात विकास रोकने की नहीं, उसे पहाड़ की प्रकृति के मुताबिक ढालने की है। हिमाचल की 2023 की बाढ़ पर 2025 में ऑल अर्थ में प्रकाशित एक अध्ययन ने भी दिखाया कि तबाही को केवल बारिश से समझना पर्याप्त नहीं है। अध्ययन के सांख्यिकीय मॉडल में वर्षा की तीव्रता और वनस्पति क्षरण जैसे कारकों ने बाढ़ की गंभीरता में देखी गई करीब 85 प्रतिशत भिन्नता को समझाने में योगदान दिया। यह 85 प्रतिशत नुकसान को मानवजनित बताने वाला आंकड़ा नहीं है।

इसका संकेत इतना भर है कि बारिश प्राकृतिक हो सकती है, लेकिन उसकी मारक क्षमता जमीन, जंगल और ढलानों की स्थिति से भी तय होती है। सितंबर के अंतरराष्ट्रीय दिवस भी इसी सवाल की अलग-अलग तस्वीर दिखाते हैं। 20 सितंबर का विश्व क्लीनअप दिवस पहाड़ों में बढ़ते कचरे की चुनौती की याद दिलाता है, जबकि 27 सितंबर का विश्व पर्यटन दिवस उस अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान खींचता है, जिसकी हिमाचल में बड़ी भूमिका है। सवाल यह है कि पर्यटन बढ़े, लेकिन उसकी कीमत पहाड़ को न चुकानी पड़े। हिमाचल की रीढ़ कहे जाने वाला पर्यटन ही यहां लाखों लोगों के रोजगार और कमाई का मुख्य सहारा है। लेकिन किसी शांत घाटी में पर्यटक बढ़ें और पानी, पार्किंग, सीवेरेज, कचरा, सडक जैसी सुविधाएं न बढ़ें, तब पर्यटन रोजगार का अवसर होने के बजाय स्थानीय संसाधनों पर बोझ बढ़ाने लगता है। मनाली से अटल टनल तक और कसोल-तीर्थन घाटी में बढ़ते निर्माण और मलबे की समस्या संकेत देती है कि जब पर्यटन स्थानीय वहन क्षमता से आगे निकलता है, तो रोजगार के साथ पर्यावरणीय और आपदा संबंधी जोखिम भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए अब हिमाचल को यह तय करना होगा कि किसी घाटी, कस्बे या नदी के लिए कितनी सडक, कितने होटल, कितनी गाड़ियां, कितने पर्यटक और कितना निर्माण सुरक्षित है। इसका जवाब सिर्फ बाजार या इंजीनियरिंग नहीं दे सकती, पहाड़ की अपनी प्राकृतिक सीमाएं भी इसे तय करेंगी। यही बात कचरे पर भी लागू होती है। कचरा भी पहाड़ की वहन-क्षमता की परीक्षा है। पर्यटन स्थलों का प्लास्टिक और कचरा नदियों, खड्डों और खेतों तक पहुंचता है। इसलिए सडक, होटल और पर्यटकों की संख्या तय करते समय कचरा प्रबंधन की क्षमता भी देखनी होगी।

जरूरी है कि जलस्त्रोतों पर कब्जा रोका जाए, संवेदनशील ढलानों की पहचान हो, मलबा फेंकने के नियम सख्ती से लागू हों और नदी-खड्डों का प्राकृतिक दायरा सुरक्षित रखा जाए। पंचायतों और स्थानीय समुदायों को निगरानी में असली भूमिका मिले, क्योंकि पहाड़ की नब्ज वही बेहतर समझता है जो पीढ़ियों से उसके साथ जी रहा है। आपदा से पहले तैयारी, वैज्ञानिक भू-उपयोग योजना और निर्माण नियमों का प्रभावी अनुपालन ही आपदा के जोखिम को कम कर सकता है। राहत और मुआवजा जरूरी हैं, पर वे स्थायी हल नहीं। हिमाचल को ऐसा विकास चाहिए जिसमें सडक भी बने, रोजगार भी मिले, पर्यटन भी बढ़े और पहाड़ भी सलामत रहे। रफ्तार जरूरी है, पर दिशा उससे भी ज्यादा जरूरी है। हिमालय सिर्फ सैरगाह नहीं, जीवन की डोर है। सवाल यह नहीं कि पहाड़ विकास के साथ चलेंगे या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम विकास को पहाड़ की मयार्दा में चलाना सीखेंगे?

विशेष स्कीम पर भारतवंशियों को भरोसा

डा. अश्विनी महाजन

आरबीआई पर आने वाली लागत का मुद्दा है। आलोचक मान रहे हैं कि चूंकि आरबीआई की स्पेशल स्वैप व्यवस्था के तहत बैंकों को हेजिंग की लागत नहीं उठानी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि हेजिंग की लागत अब आरबीआई को उठानी पड़ेगी, जो असल में सही नहीं है। सच तो यह है कि ये डिपॉजिट विदेशी मुद्रा भंडार (फॉरेक्स रिजर्व) बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आरबीआई के पास रहेगा, जिसे यदि अमरीकी फेडरल रिजर्व में जमा किया जाएगा तो उस पर 5 से 6 प्रतिशत ब्याज मिलेगा।

वर्ष 2013 में भी जब देश विदेशी मुद्रा भंडार संकट से गुजर रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग इसी प्रकार की विशेष स्वैप स्कीम के माध्यम से मात्र 85 दिनों में ही 34.3 अरब डॉलर जुटाए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के माध्यम से आए थे

आठ जून से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक विशेष स्वैप स्कीम की शुरूआत की और बैंकों को यह सुविधा दी कि इस स्कीम के तहत भारतवंशी यानी विदेश में भारतीय मूल के लोगों द्वारा भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा जमा (3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि के लिए) को वर्तमान मूल्य से रिजर्व बैंक से स्वैप कर पाएंगे। यानी जिस मूल्य पर आज बैंक रिजर्व बैंक के पास जमा करेंगे, परिपक्व होने पर उसी मूल्य पर वे रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर पाएंगे। इस स्कीम से प्रोत्साहित होकर बैंकों ने भारतवंशियों की जमाएं 6 से 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर स्वीकार की, जिन पर पूर्व में केवल तीन से चार प्रतिशत ही ब्याज दिया जाता था। इसका कारण यह था कि रुपए में डॉलर के मूल्य बढ? के जोखिम के लिए बैंकों को पहले हेजिंग करवानी पड़ती थी। हेजिंग की लागत समय-समय पर बदलती रही है, लेकिन वर्तमान समय में यह तीन प्रतिशत के आसपास है। इन विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खातों पर अधिक ब्याज और दूसरी ओर भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकार और बैंकों पर भरोसा, इन सभी कारणों से भारतवंशियों ने मात्र 3 महीने से भी कम समय में 127.2 अरब डॉलर जमा कर इतिहास रचा है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में भी लगभग इसी प्रकार की स्कीम के अंतर्गत मात्र 34.3 अरब डॉलर एकत्र हुए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के रूप में प्राप्त हुए। 2013 में यह स्कीम 85 दिनों तक खुली रही थी और 2026 की स्कीम भी 85 दिन चली, लेकिन इन 85 दिनों में एफसीएनआर खातों में कुल जमा 127.2 अरब डॉलर प्राप्त हुए, जबकि कुल प्राप्तियां 136.4 अरब डॉलर की रही। यानी 2026 में 2013 की तुलना में लगभग 4.9 गुना ज्यादा। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम इस बार काफी सफल रही और उसके परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। लेकिन आर्थिक जगत के कुछ लोगों द्वारा इस स्कीम की आलोचना भी की जा रही है। आलोचकों का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को हेजिंग लागत से मुक्त कर, वह भार स्वयं पर ले लिया है। जिसका खामियाजा रिजर्व बैंक को भविष्य में भुगतना पड़ेगा और जब ये जमाएं परिपक्व होंगी और डॉलर का मूल्य रुपयों में अधिक होगा तो नुकसान रिजर्व बैंक के लाभों को कम कर देगा। फलस्वरूप रिजर्व बैंक के लाभ कम होने से भारत सरकार की प्राप्तियां घट जाएंगी, जिससे बजट असंतुलन हो जाएगा।

क्यों सही नहीं हैं आलोचकों के तर्क : लोकतंत्र में नीतियों पर बहस एक स्वस्थ परंपरा है, लेकिन आलोचकों के तर्कों की सत्यता की पड़ताल भी उतनी ही जरूरी है, ताकि नीतियों को सही दिशा दी जा सके। रिजर्व बैंक की विशेष स्वैप स्कीम के लाभों पर चर्चा भी जरूरी है। फिर यह देखना होगा कि भविष्य में रिजर्व बैंक को इससे जिस संभावित नुकसान की चिंता की जा रही है, उसकी तुलना में इस योजना से कितना लाभ देश को होगा।

पूर्व में भी ऐसी स्कीम हुई थी सफल : वर्ष 2013 में भी जब देश विदेशी मुद्रा भंडार संकट से गुजर रहा था, भारतीय रिजर्व बैंक के लगभग इसी प्रकार की विशेष स्वैप स्कीम के माध्यम से मात्र 85 दिनों में ही 34.3 अरब डॉलर जुटाए थे, जिनमें 26 अरब डॉलर एफसीएनआर के माध्यम से आए थे। उस समय विदेशी विनिमय में भयंकर अनिश्चितता का माहौल था। इस स्कीम से पहले सामान्यतः करेंसी का जोखिम बैंकों को उठाना पड़ता था, इसलिए वे एफसीएनआर पर अत्यंत सीमित ब्याज दे पाते थे। 2013 की स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह गारंटी दी थी कि भविष्य में जब भी यह जमा 3 से 5 वर्ष के बीच परिपक्व होगी, रिजर्व बैंक उनसे 3.5 प्रतिशत वार्षिक ही वसूलेगा। इससे प्रोत्साहित होकर बैंकों ने ज्यादा ब्याज देकर एफसीएनआर जमाई बढ़ाने का प्रयास किया। वर्ष 2013-14 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्वीकार किया था कि इस विशेष स्वैप स्कीम के तहत विदेशी मुद्रा भंडार बढ? से रुपए को स्थिरता प्राप्त हुई। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में सितंबर माह (जब यह स्कीम शुरू हुई थी) से पहले रुपए में तेजी से अवमूल्यन हो रहा था और अप्रैल 2013 से अगस्त तक रुपए का 16.2 प्रतिशत अवमूल्यन हो चुका था। लेकिन इस स्कीम और अन्य उपायों के फलस्वरूप विदेशी परिस्थितियों के बावजूद सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच रुपया 9.7 प्रतिशत मजबूत हुआ और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार, जो अगस्त तक 275.5 अरब डालर था, जनवरी 2014 तक वो 292.1 अरब डालर तक पहुंच गया। समझना होगा कि 2013 की विशेष स्वैप स्कीम के कारण रुपए में मजबूती के फलस्वरूप भारत का पेट्रोलियम तेल और सोने की आयात लागत घटी। सरकारों और विदेशी ऋणों की अदायगी में लाभ हुआ, आयातित मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा। विदेशों से पूंजी सस्ती हुई और चालू खाते पर दबाव घटा। इसलिए जो लोग रिजर्व बैंक द्वारा गारंटीशुदा कम स्वैप लागत की आलोचना कर रहे थे, उनके तर्क असत्य साबित हुए। और यदि रिजर्व बैंक द्वारा इस स्वैप स्कीम पर खर्च की तुलना, इस स्कीम के कारण देश पर आए विदेशी मुद्रा संकट से निजात, और देश को भारी लाभ से करें तो यह योजना लाभकारी ही मानी जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे दुनिया की 5 सर्वाधिक कमजोर अर्थव्यवस्था में माना जा रहा था, उसे विदेशी मुद्रा संकट से बचाने में इस स्कीम की महती भूमिका रही।

वर्तमान विशेष स्वैप स्कीम और उसके फायदे : सर्वप्रथम, इससे रुपया मजबूती की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान स्वैप स्कीम ऐसे समय में लाई गई जब विदेशी संस्थागत निवेश का लगातार बिकवाली कर सरकार द्वारा दबाव बना रहे थे कि उन्हें करों में रियायत दी जाए। सरकार को मजबूरी में कुछ रियायत देनी भी पड़ी थी। यही नहीं, युद्ध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, तेल की बढ़ती कीमतों और अन्य वैश्विक कारणों से हमारा विदेशी व्यापार संतुलन बिगड़ रहा था, उस समय हमारा भारतीय रुपया लगातार कमजोर हो रहा था और वह 1 जनवरी 2026 में 89.50 रुपए प्रति डॉलर से कमजोर होते हुए 20 मार्च 2026 तक 96.96 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुका था। ऐसे में रुपए को स्थिरता से बचाने के लिए रिजर्व बैंक को भारी मात्रा में डॉलर बेचने पड़ रहे थे, जिनके कारण भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संकट मंडराने लगा था।

उन परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ने विशेष स्वैप स्कीम के तहत 136.4 अरब डॉलर की प्राप्तियां, जिनमें 127.2 अरब डॉलर केवल एफसीएनआर बैंक जमा से मिले, डालरों के इस भारी अंतरप्रवाह के कारण, इस स्कीम के प्रारंभ से ही रुपया मजबूत होने लगा था। 5 सितंबर 2026 तक आते-आते यह 94.49 रुपए प्रति डॉलर तक पहुंच चुका था। मजबूत रुपए के स्वाभाविक लाभों के बारे में कोई संदेह नहीं है। दूसरे, ऐतिहासिक रूप से एफसीएनआर डिपॉजिट में एफपीआई निवेश की तरह उतार-चढ़ाव (वोलाटिलिटी) बहुत कम देखा जाता है। समझ से परे है कि जब आलोचकों को एफपीआई को ब्याज और कैपिटल गेन पर टैक्स छूट के रूप में लगातार फायदा देने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो वे एफसीएनआर-बी को दी गई रियायतों को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं?

न्यूज ब्रीफ

ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रम में संबोधन के दौरान हंगामा

ग्वालियर। ग्वालियर के गिरवाई क्षेत्र में कुशवाह समाज के छात्रावास सह–सामुदायिक भवन के भूमिपूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का उद्बोधन शुरू होते ही कुछ युवाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। अग्रिम पंक्ति में बैठे इन युवाओं ने शोर–शराबे के बीच राजनीति नहीं चलेगी और समाज को बांटना बंद करो जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि कुछ युवाओं के हाथ में काले झंडे भी थे। आयोजकों ने पुलिस की मदद से इन युवाओं को पंडाल से बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई और कुर्सियां भी फेंकी गईं। इस हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें पुलिस युवाओं को खींचकर ले जाने का प्रयास कर रही है, जबकि कुछ आयोजक उनकी पिटाई करने की कोशिश कर रहे हैं ।हंगामे के बीच सिंधिया ने मंच से कहा कि इन्हें अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हंगामा करने वालों के नाम और उन्हें भेजने वाले का नाम नोट कर लिया गया है। पुलिस ने इन युवाओं को गिरवाई थाने ले जाकर पूछताछ की।

ग्वालियर विधानसभा में 24 एवं 25 सितम्बर को जल प्रदाय रहेगा प्रभावित

ग्वालियर। 160 एमएलडी जल शोधन संयंत्र जलालपुर से ग्वालियर विधानसभा की ओर जाने वाली 800 एमएम व्यास की पम्पिंग मैन लाइन से चार शहर का नाका चौराहे पर 600 एमएम व्यास की नवीन डीआई पाईप लाईन से मिलान कार्य के चलते ग्वालियर विधानसभा में दिनांक 24 एवं 25 सितम्बर को जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। कार्यपालन यंत्री शिशिर श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 160 एमएलडी जल शोधन संयंत्र जलालपुर से ग्वालियर विधानसभा की ओर जाने वाली 800 एमएम व्यास की पम्पिंग मैन लाइन से चार शहर का नाका चौराहे पर 600 एमएम व्यास की नवीन डीआई पाईप लाईन से मिलान कार्य हेतु दिनांक 23.09.2026 से 24.09.2026 तक दो दिवस का शटडाउन लिया जाना है, जिस कारण दिनांक 24.09.2026 को होने वाला सीधा जल प्रदाय एवं 25.09.2026 को टंकियों के माध्यम से ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में होने वाला जल प्रदाय प्रभावित रहेगा।

अपर आयुक्त प्रदीप सिंह तोमर ने सुनी आमजन की समस्याएं

ग्वालियर। आमजनों की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जनसुनवाई आयोजित की गई। जिसमें नगर निगम ग्वालियर में प्रदीप सिंह तोमर एवं मुनीष सिकरवार ने आमजनों की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जनसुनवाई के दौरान अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। सिटीसेंटर स्थित निगम मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई में लाल टिपारा क्षेत्र के निवासियों द्वारा की गई शिकायत में बताया गया है कि ग्रामीणों द्वारा भैंसों का गोबर स्कूल परिसर में डाला जा रहा है, जिसके कारण स्कूल में गंदगी रहती है, साथ ही बाउण्ड्रीवाल भी टूट गई है। साथ ही विधालय के मार्ग में गोबर डाल दिए जाने के कारण विधालय में पढने के लिए आने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इसके साथ ही वार्ड 61 वैष्णो धाम कॉलोनी न्यू सिरोल थाने के सामने के निवासी गणों ने सचिन तेन्दुलकर मार्ग न्यू सिरोल थाना फूटी कॉलोनी से आगे वैष्णो धाम कॉलोनी में मैन रोड पर किये जा रहे अवैध निर्माण को हटवाये जाने के संबंध में, वार्ड 6 प्रजापति मोहल्ला जहांगीर कटरा निवासी श्री जगदीश प्रजापति ने आवेदन देकर शासकीय भूमि पर किये जा रहे अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में, वार्ड 19 महावीर नगर निवासी श्री विजेन्द्र सिंह ने आवेदन देकर बताया कि महावीर नगर लोधी चौक पर काफी दिनों से सीवर सडक पर बह रहा है, आवेदक ने सीवर सफाई कराये जाने के संबंध में अपना आवेदन अपर आयुक्त को दिया। इसके साथ ही विभिन्न समस्याओं से संबंधित 39 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश अपर आयुक्त ने दिए।

हिंदू महासभा ने प्रदर्शन कर निगम प्रशासन का पुतला जलाया

ग्वालियर। गणेश विसर्जन के लिए सड़कों के गड्ढे ठीक करने, डेली नलों में पानी देने, कमरतोड़ महंगाई एवं 205 लाख करोड रुपए के विदेशी कर्ज से मुक्ति के लिए हिंदू महासभा अपना चरण बद्ध आंदोलन चला रही है। हिंदू महासभा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी को पत्र लिखकर चार दिन में मांगों का समाधान करने का आग्रह पत्र दिया था। आज आकोर्षित हिंदू महासभाइयों ने 22 सितंबर को सुबह 8 :00 बजे रामदास घाटी पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रदर्शन करते हुए निगम प्रशासन का पुतला जलाते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के पुतले को जलाने की घोषणा करते ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं निगम प्रशासन सक्रिय हो गया और श्रीमान आयुक्त अभिषेक चौधरी ने अपर आयुक्त डॉ प्रदीप सिंह तोमर को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचाकर समाधान करने का निर्देश दिए ।उपाध्यक्ष डॉ जयवीर भारद्वाज ने अपर

फर्जी दस्तावेजों से 17 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने का मामला

थाना प्रभारी और आरक्षक पर गिरेगी गाज, एसटीएफ अधिकारियों ने मांगी विभागीय जांच

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जाली दस्तावेजों के जरिए बांग्लादेशी नागरिकों के हिंदू नाम से पासपोर्ट बनवाने के बहुचर्चित मामले में अब जांच की आंच पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई है। ग्वालियर के डबरा स्थित बौद्ध विहार के एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर 17 बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाए गए थे। इस गंभीर लापरवाही पर एसटीएफ (स्त्रस्न) ने कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन डबरा थाना प्रभारी और पुलिस सत्यापन करने वाले आरक्षक के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति की है। एसटीएफ की जांच और पुलिसकर्मियों की लापरवाही डबरा के बौद्ध विहार पते पर पासपोर्ट बनवाकर ये बांग्लादेशी नागरिक चीन, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों की यात्राएं भी कर आए, जिनमें से कई विदेश भाग चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ डीआईजी राहुल लोढ़ा ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह को पत्र लिखकर तत्कालीन डबरा थाना प्रभारी विनायक शुक्ला और पासपोर्ट सत्यापन का कार्य देख रहे आरक्षक भूपेंद्र गुर्जर की प्राथमिक व विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ अधिकारियों का कहना है कि यदि पुलिस सत्यापन के दौरान ही दस्तावेजों और एक ही मोबाइल नंबर की बारीकी से जांच कर ली जाती, तो यह फर्जीवाड़ा शुरुआती स्तर पर ही पकड़ में आ जाता और बौद्ध भिक्षु बनकर रह रहे ये विदेशी नागरिक आसानी से पासपोर्ट नहीं बनवा पाते। भोपाल और बैतूल के मामलेः भोपाल के गोविंदपुरा स्थित अन्नानगर बौद्ध मठ से 40 और बैतूल से 11 बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट बनवाए गए। इन मामलों में भी पुलिस सत्यापन के दौरान गंभीर लापरवाही बरती गई। जिम्मेदारों पर शिकंजाः एसटीएफ डीआईजी ने भोपाल के तत्कालीन गोविंदपुरा थाना प्रभारी, बैतूल के संबंधित थाना प्रभारियों और पासपोर्ट सेल प्रभारियों की जांच के लिए भी पत्र लिखे हैं। 'बंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों से इन पुलिसकर्मियों की विभागीय जांच रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके तहत उन्हें नोटिस जारी कर एसटीएफ द्वारा उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए भोपाल के एजेंट नसीम अख्तर से पूछताछ में पासपोर्ट सेवा केंद्र के एक कर्मचारी का नाम सामने आया है, जो वर्तमान में पंजाब-हरियाणा बॉर्डर के जिले में पदस्थ है। उसकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। एसटीएफ एडीजी डी. वर्मा का कहना है कि पुलिस सत्यापन में हुई भारी चूक के कारण ही ये पासपोर्ट जारी हुए।

आयुष्मान योजना के निजी अस्पतालों के लिए NABH प्रमाण पत्र अनिवार्य

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आयुष्मान योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक सख्त और नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब इन महानगरों के अनुबंधित निजी अस्पतालों में 'मेडिसिन के पैकेज' के तहत उपचार देने के लिए एनएबीएच का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नई व्यवस्था आगामी 1 अक्टूबर से प्रभावी होने जा रही है। तय समय-सीमा में प्रमाण पत्र न होने के कारण अकेले ग्वालियर के लगभग 79 निजी अस्पताल इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएंगे, जिससे अस्पताल संचालकों में खासी चिंता और हलचल पैदा हो गई है। निजी अस्पताल संचालकों और प्रबंधनों का कहना है कि एनएबीएच की पूरी प्रक्रिया और मानक को पूरा करने में काफी समय लगता है, और सभी अस्पतालों के लिए रातों-रात या इतनी जल्दी यह प्रमाणपत्र हासिल करना व्यावहारिक रूप से आसान नहीं है। इस गंभीर समस्या के समाधान और सरकार के इस फैसले पर चर्चा के लिए निजी अस्पतालों से जुड़े संगठनों की एक अहम बैठक 27 सितंबर को प्रस्तावित की गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार के समक्ष समय-सीमा बढ़ाने व राहत देने की मांग प्रमुखता से रखी जाएगी। हालांकि, जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत आने वाले मरीजों की संख्या बहुत अधिक है और जो लगातार भारी संख्या में इलाज कर रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से एंट्री-लेवल एनएबीएच की प्रक्रिया अभी से शुरू कर दी है। राकेश रायजादा ने बताया कि 27 सितंबर को होने वाली बैठक में सरकार के निर्णय के खिलाफ व्यावहारिक कठिनाइयों को सामने लाने और आवश्यक मोहलत मांगने पर विचार-विमर्श होगा।

लैट की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर बैंक में गिरवी रखकर हड़पे 45.50 लाख रुपये, आठ के खिलाफ केस दर्ज

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के साकेत नगर में एक फ्लैट की फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर उसे बैंक में गिरवी रखकर करीब 45.50 लाख रुपये का लोन लेने का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस धोखाधड़ी में शामिल कुल आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। साकेत नगर स्थित जी-1/85 'प्रतिमा विला' फ्लैट की वास्तविक मालकिन पूर्णिमा गुप्ता हैं। उन्होंने यह फ्लैट राघवेंद्र सिंह सेंगर से 27 जून 2019 को एक वैध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए खरीदा था, जिसके बाद वे अपने परिवार के साथ वहां रहने लगीं और वर्ष 2022 में नगर निगम में इसका नामांतरण भी करवा लिया था। कुछ समय पहले जब पीड़िता को यह जानकारी मिली कि उनके

इसी फ्लैट की एक अन्य फर्जी रजिस्ट्री भी बाजार में मौजूद है, तो उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 19 मार्च 2019 की तारीख में एक दूसरी फर्जी रजिस्ट्री तैयार की गई थी। इस जाली दस्तावेज में विक्रेता राघवेंद्र सिंह द्वारा संतोष राज अग्रवाल और नीलम अग्रवाल के पक्ष में फ्लैट का बेचना दर्शाया गया था। इसी फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर पंजाब एंड सिंध बैंक से लोन लिया गया, और बैंक रिकॉर्ड में लगभग 22.50 लाख रुपये का लोन स्वीकृत होने तथा अलग-अलग खातों से भुगतान का जिक्र किया गया। वास्तविक रजिस्ट्री में फ्लैट का क्षेत्रफल 65.04 वर्गमीटर है, जबकि फर्जी रजिस्ट्री में इसे बढ़ाकर 69.70 वर्गमीटर दर्ज किया गया था। इसके अलावा फ्लैट की चारों सीमाओं में भी भारी अंतर मिला। फोटोज और भुगतान में गड़बड़ीः फर्जी रजिस्ट्री में विक्रेता राघवेंद्र सिंह की फोटो भी मूल दस्तावेज में लगी तस्वीर से अलग पाई गई। संबंधित बैंक खातों की जांच करने पर उस खाते से किसी भी प्रकार के वास्तविक भुगतान का रिकॉर्ड नहीं मिला।

स्वाइन फ्लू और डेंगू का प्रकोपः जेल कैदी और दिल्ली से लौटी महिला समेत नए मरीज मिले

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बदलते मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच मौसमी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ गया है। बीते 24 घंटों के दौरान स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू के 2 और डेंगू के 2 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के नए मामलों में ग्वालियर केंद्रीय जेल में बंद एक पुरुष और दिल्ली से लौटकर आई एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं। इसके साथ ही जिले में इस साल अब तक डेंगू के कुल 98 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और जीआरएमसी वायरोलॉजी लैब से प्राप्त आंकड़ों के अनुसारः डेंगू का संक्रमणः डेंगू के 2 नए मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। इनमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है, जिसे रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वाइन फ्लू के 2 नए मामलों को मिलाकर इस सीजन में अब तक कुल 10 मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इनमें से पहले भर्ती किए गए 2 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। इसके अलावा, इस सीजन में अब तक चिकनगुनिया के भी 6 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। स्वाइन फ्लू और डेंगू के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क मोड पर आ गए हैं। सभी नए मरीजों को विशेष रूप से बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। उनकी सेहत पर लगातार नजर रखने के लिए वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष टीम को तैनात किया गया है। इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी पैथोलॉजी सेंटरों से भी रोजाना की रिपोर्टिंग का डेटा एकत्र किया जा रहा है।

ग्वालियर में अचलेश्वर न्यास चुनाव की तारीख तय, 11 अक्टूबर को मतदान, तैयारियां तेज

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

श्री अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक न्यास, ग्वालियर की नई कार्यकारिणी के गठन का रास्ता साफ हो गया है। न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए इस बहुप्रतीक्षित चुनाव के लिए मतदान 11 अक्टूबर 2026 को ही आयोजित किया जाएगा। जिला न्यायालय द्वारा चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और निर्वाचन समिति ने अपनी तैयारियां बेहद तेज कर दी हैं। शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र साहू के माध्यम से प्रस्तुत की गई चुनाव समिति, निर्वाचन कार्यक्रम और नियमावली को न्यायालय ने आधिकारिक रूप से अनुमोदित कर दिया है। इस चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी मुख्य तिथियां इस प्रकार हैंः मतदान स्थलः मतदान की प्रक्रिया शहर के एमएलबी कॉलेज में संपन्न होगी।मतदाता सूची पर आपत्तिः मतदाता सूची पर किसी भी प्रकार की आपत्ति 23 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक दर्ज कराई जा सकेगी। अंतिम सूची और प्रत्याशियों का ऐलानः आपत्तियों का निराकरण करने के बाद उसी दिन अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी, जबकि प्रत्याशियों की अंतिम सूची 30 सितंबर को घोषित की जाएगी। न्यायालय के इस स्पष्ट आदेश के बाद अचलेश्वर न्यास चुनाव को लेकर शहर के धार्मिक और सामाजिक हलकों में गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं।

मुरार में पैसों के विवाद को लेकर घर पर 10-12 राउंड फायरिंग, बिना नंबर की गाड़ी से आए थे बदमाश

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के मुरार थाना क्षेत्र स्थित एसएलपी कॉलेज के पास लोचन नगर में सोमवार देर रात ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। पैसों के लेनदेन के पुराने विवाद को लेकर बिना नंबर की गाड़ी से आए बेखौफ बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए 10 से 12 राउंड गोलियां दाग दीं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हवा में हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। लोचन नगर निवासी पीड़िता जूली ने पुलिस को बताया कि उनका राहुल गुर्जर (निवासी पारसेन) नामक युवक के साथ पैसों के लेनदेन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है। आरोप है कि राहुल पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके पति और देवर का पीछा कर रहा था और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा था।

सोमवार की रात आरोपी अपनी बिना नंबर की गाड़ी से कुछ साथियों के साथ पहुंचा और घर के बाहर आते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हुई गोलीबारी से पूरे इलाके में भारी दहशत फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए। इस बीच, मुरार थाने में पुष्पेन्द्र घुरैया नामक एक युवक पहुंचा, जिसके शरीर पर छर्रे लगने की बात सामने आई है। उसका कहना है कि वह किसी राहुल को नहीं जानता, जिसके चलते पुलिस इस उलझन में है और मामले की हर एंगल से गहराई से छानबीन कर रही है। वारदात की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास की सड़कों से गोलियों के खाली खोके बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया है। आरोपियों की पहचान करने और उनकी आवाजाही का रूट पता करने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

ग्वालियर में सनसनीखेज वारदात

कॉलेज छात्रा से गैंगरेप, काम का झांसा देकर देर शाम रोका, दो आरोपी गिरफ्तार

■ एक सत बुलेटिन, ग्वालियर

मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ई-कॉमर्स कंपनी के एक वेयरहाउस में 21 वर्षीय कॉलेज छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। वेयरहाउस संचालकों ने 'काम ज्यादा है' का बहाना बनाकर छात्रा को देर शाम तक रोक लिया और सभी कर्मचारियों के जाने के बाद अंदर से चैनल गेट बंद कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गोला का मंदिर थाना पुलिस के मुताबिक, यह वारदात 17 सितंबर की शाम करीब 7 बजे पटरी रोड स्थित एक वेयरहाउस में हुई। पीड़ित छात्रा बीए प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही है और अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए वहां पार्ट-टाइम काम करती थी। घटना वाले दिन जब छुट्टी का समय हुआ, तो वेयरहाउस संचालक आदित्य भदौरिया और रोबिन शर्मा ने उसे रोक लिया। अन्य सभी कर्मचारी काम

खत्म करके चले गए, जिससे वेयरहाउस में केवल छात्रा और दोनों संचालक ही बचे। इसके बाद दोनों ने अंदर से चैनल गेट बंद कर दिया। छात्रा द्वारा विरोध करने पर उसे डराया-धमकाया गया और दुष्कर्म के बाद किसी को भी बताने पर जान से मारने की गंभीर धमकी दी गई। इसी खौफ के कारण पीड़िता कई दिनों तक सहमी रही और चुपचाप बैठी रही। घटना के बाद पीड़िता के व्यवहार और उसकी मानसिक हालत में आए भारी बदलाव को देखकर परिजनों को संदेह हुआ। उन्होंने जब उससे सख्ती से पूछताछ की, तो उसने रोते हुए पूरी आपबीती परिजनों को बताई। इसके बाद सोमवार को पीड़िता अपने परिजनों के साथ गोला का मंदिर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने जानकारी दी कि आदित्य भदौरिया और रोबिन शर्मा पार्टनरशिप में इस वेयरहाउस का संचालन करते हैं, जो महज 15 दिन पहले ही शुरू किया गया था। इस वेयरहाउस में ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का काम होता है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवा लिया है और दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप व जान से मारने की धमकी की धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया है।

संक्षिप्त समाचार

टेबल टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से धोया

सुतीर्था-सिंड्रेला और श्रीजा की तिकड़ी ने किया कमाल

नागोया । एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन की शुरुआत भारतीय टेबल टेनिस टीम ने धमाकेदार जीत के साथ की है। सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला की तिकड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 3-0 से रौंदा। सुतीर्था मुखर्जी ने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान पाकिस्तान की खिलाड़ी अलीना सुतीर्था के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आईं। सुतीर्था पूरे मैच में हावी

रहीं और उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सुतीर्था ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पहले गेम को 11-3 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी सुतीर्था का दबदबा देखने को मिला और उन्होंने यह गेम 11-3 से जीता। तीसरे गेम को 11-4 से जीतने के साथ ही सुतीर्था ने मैच को अपने नाम करते भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे मुकाबले में सिंड्रेला दास ने दमदार प्रदर्शन किया। भारतीय युवा खिलाड़ी सिंड्रेला ने पाकिस्तान की कुलसूम खान के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाया और उन्हें आसानी से 11-6, 11-7, 11-5 से शिकस्त देते हुए भारत को मुकाबले में 2-0 की बढ़त दिलाई।

ओडिशा टी20 लीग

गौरव चौधरी ने खेली धमाकेदार पारी

संबलपुर वॉरियर्स ने कटक पैंथर्स को 9 रनों से हराया

कटक । संबलपुर वॉरियर्स ने ओडिशा टी20 लीग की शुरुआत जीत के साथ की है। टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बाराबती स्टेडियम में कटक पैंथर्स को 9 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉरियर्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 193 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। टीम के कप्तान गौरव चौधरी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 88 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी इस पारी में 9

चौके और 6 छक्के लगाए। गौरव चौधरी को शांतनु मिश्रा का अच्छा साथ मिला, और दोनों ने मिलकर 135 रनों की शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप की। आउट होने से पहले शांतनु ने 40 गेंदों में 60 रन बनाए, जबकि गौरव तेजी से स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि, कप्तान के पवेलियन लौटने के बाद वॉरियर्स की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई और टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए। हालांकि, इसके बावजूद टीम 193 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही। अभिषेक सिंह कटक पैंथर्स की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे और उन्होंने 4 ओवर में 32 रन देकर 3 विकेट चटकाए।

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय शूटर्स का दमदार प्रदर्शन जारी

हिमांशु ने सिल्वर और रुद्राक्ष ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

नागोया । एशियन गेम्स 2026 में सोमवार को पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भारत ने दो पदक हासिल किए। एक कड़े मुकाबले के बाद हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर मेडल और रुद्राक्ष पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हिमांशु ने कुल 252.4 प्वाइंट्स अर्जित किए और वह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि रुद्राक्ष 230.9 प्वाइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चीन के मौजूदा ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ ने 254.2 के गेम्स रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता और सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। आठ खिलाड़ियों के फाइनल में भारतीय जोड़ी शुरू से ही मेडल की दौड़ में बनी हुई थी, जिसमें रुद्राक्ष ने बहुत अच्छी शुरुआत की। शुरुआती 10 शॉट्स के बाद वह 106.0 प्वाइंट्स के साथ सबसे आगे थे, उनके बाद शेंग 104.9 प्वाइंट्स और हिमांशु 104.8 प्वाइंट्स के साथ थे। एलिमिनेशन राउंड शुरू होने पर भी भारतीय खिलाड़ी टॉप दो स्थानों पर काबिज रहे। रुद्राक्ष आगे बने रहे, जबकि हिमांशु ने लगातार अच्छे स्कोर किए, जिसमें लगातार 10.9 प्वाइंट्स के स्कोर भी शामिल थे, जिससे वह दूसरे स्थान पर आ गए। शेंग ने जैसे-जैसे अंतर कम किया, बढ़त बार-बार बदलती रही। दूसरे एलिमिनेशन के बाद भी रुद्राक्ष टॉप पर थे और हिमांशु तीसरे स्थान पर थे, लेकिन आखिरकार चीनी शूटर पहले स्थान पर आने में सफल रहा।

जब मुकाबले में सिर्फ चार शूटर बचे थे, तब मंगोलिया के बयारा न्यंतई के बाहर होने के साथ ही भारत का डबल पोडियम स्थान पक्का हो गया। उस समय चीन के शेंग 211.6 अंकों के साथ पहले स्थान पर थे, जबकि भारत के रुद्राक्ष 210.6 और हिमांशु 210.0 अंकों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर चल रहे थे। इससे भारत के दो पदक सुनिश्चित हो गए।

इसके बाद सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला शेंग के पीछे पूरी तरह से भारतीयों के बीच सिमट गया। हिमांशु ने रुद्राक्ष से बढ़त बना ली, जब उन्होंने 10.8 प्वाइंट्स का स्कोर किया और रुद्राक्ष ने 9.7 प्वाइंट्स का स्कोर किया, जिससे रुद्राक्ष तीसरे स्थान पर खिसक गए। रुद्राक्ष ने एलिमिनेशन शॉट पर 10.6 प्वाइंट्स के साथ वापसी की कोशिश की, लेकिन हिमांशु ने 10.4 प्वाइंट्स के साथ अपनी स्थिति बनाए रखी। शेंग ने आखिरी शॉट में 10.6 का स्कोर करके गोल्ड मेडल पक्का किया और 254.2 के गेम्स रिकॉर्ड के साथ मुकाबला खत्म किया। हिमांशु, जिन्होंने अपने दूसरे आखिरी शॉट से शेंग की बढ़त को 1.8 प्वाइंट तक कम कर दिया था, 252.4 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रुद्रांक्ष ने कुल 230.9 का स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल जीता।

हिमांशु ढिल्लों ने भी जताई खुशी

भारतीय निशानेबाज हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स 2026 में दो सिल्वर मेडल जीतने को अपने लिए गर्व का पल बताया। हिमांशु ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम और व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। हिमांशु ने कहा कि देश के लिए कुछ हासिल करने पर भावुक होना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि यह सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका पहला व्यक्तिगत पदक है और दो मेडल जीतना उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा कि सफलता का आनंद लेने के साथ आगे की प्रतियोगिताओं पर ध्यान बनाए रखना जरूरी है।

पहला एशियन गेम्स मेडल पाकर खुश हैं पार्थ

टीम सिल्वर जीतने के बाद पार्थ माने ने इसे अपने लिए बेहद खास बताया। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'यह मेडल मेरे

लिए बहुत महत्वपूर्ण और खास है, क्योंकि सीनियर टीम के साथ और यह एशियन गेम्स का भी मेरा पहला मेडल

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कटाया क्वार्टर फाइनल का टिकट

बांग्लादेश को 3-0 से दी शिकस्त

नागोया । एशियन गेम्स 2026 का आगाज भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने धमाकेदार जीत के साथ किया है। एकतरफा मुकाबले में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और किदांबी श्रीकांत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 3-0 से शिकस्त दी। भारत को मुकाबले में बेहतरीन शुरुआत लक्ष्य सेन ने दिलाई। बांग्लादेश के खिलाड़ी अयमान इब्न जमन के खिलाफ खेलते हुए लक्ष्य ने दमदार खेल दिखाया। पहले गेम में लक्ष्य का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला और उन्होंने एक के बाद एक दमदार शॉट्स लगाते हुए गेम को 21-4 के

बड़े अंतर से जीता। लक्ष्य अपनी इसी लय को दूसरे गेम में भी बरकरार रखने में सफल रहे। उन्होंने दूसरे गेम को 21-12 से अपने नाम करते हुए मुकाबले में भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। लक्ष्य के जबरदस्त स्मैश का जमान के पास कोई जवाब नजर नहीं आया। वहीं, बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करके सुर्खियों में आने वाले आयुष शेट्टी ने दूसरे मैच में कमाल का खेल दिखाया। बांग्लादेश के खिलाड़ी गौरव सिंघा पर आयुष पूरी तरह से हावी नजर आए और उन्होंने वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। आयुष ने पहले गेम को 21-4 से जीता। इसके बाद दूसरे गेम में भी वह अपने इस दबदबे को कायम रखने में कामयाब रहे और उन्होंने 21-13 से गेम जीतकर भारत की बढ़त को 2-0 कर डाला।

तीसरे मैच में किदांबी श्रीकांत का प्रदर्शन भी बेमिसाल रहा। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी जुमार अल-अमीन को शिकस्त देते हुए भारत की दूसरी जीत पक्की की। हालांकि, श्रीकांत को पहले गेम में जीत के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी लेकिन वह गेम को 21-15 से अपने नाम करने में सफल रहे। दूसरे गेम में श्रीकांत ने जुमार को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 21-10 से गेम को जीतकर बांग्लादेश की हार पर मुहर लगा दी। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारत की भिड़ंत अब मंगलवार को जापान से होगी।

सुचिका तरियाल के साथ हुई बेईमानी?

बराबरी का रहा मुकाबला, फिर क्यों फाइनल की रेस से हुईं बाहर?

आइची नागोया । एशियन गेम्स 2026 में भारत की सुचिका तरियाल ने पारंपरिक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी स्क्रू में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह सेमीफाइनल में हार गई और उनका फाइनल में पहुंचने का सपना बेहद नाटकीय अंदाज में टूट गया। सिंगापुर की तेओ हुई हून के खिलाफ महिलाओं की 60 किग्रा सेमीफाइनल बाउट में सुचिका मुकाबला हारकर बाहर नहीं हुईं। आधिकारिक विरोध और समीक्षा के बाद मुकाबले को ड्रॉ घोषित किया गया, लेकिन इसके बाद वजन के नियम ने फाइनलिस्ट तय किया। मुकाबले के बाद भारतीय पक्ष ने आधिकारिक विरोध दर्ज कराया। इस मामले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया गया, जिसके लिए 1,000 डॉलर की फीस जमा की गई। यह फीस महासंघ और निखिल कुंदर ने दी। इसके बाद मुकाबले के फैसले की दोबारा समीक्षा की गई।

10 जजों ने फुटेज देखकर दिया फैसला

आमतौर पर मुकाबले का फैसला तीन जजों के पैनल से होता है, लेकिन इस मामले में उपलब्ध सभी फुटेज की समीक्षा 10 जजों के पैनल ने की। समीक्षा के बाद किसी एक खिलाड़ी को विजेता नहीं चुना गया और मुकाबले को आधिकारिक तौर पर ड्रॉ घोषित किया गया।

700 ग्राम ने बदल दिया पूरा नतीजा

सुचिका अपनी सिंगापुर की प्रतिद्वंद्वी तेओ हुई हून से 700 ग्राम अधिक वजन की थीं। ड्रॉ होने के बाद वजन के नियम के तहत फैसला सिंगापुर की खिलाड़ी के पक्ष में चला गया और सुचिका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गईं। इस तरह मैट पर मुकाबला बराबरी का रहने के बावजूद सुचिका को फाइनल में जगह नहीं मिल सकी। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।

आखिरी राउंड के बाद सुचिका की आंखों में आंसू

तीसरे राउंड में तेओ ने कई किक्स लगाईं। सुचिका कुछ हद तक रक्षात्मक रहीं और निर्णायक वार के मौके का इंतजार करती रहीं। मुकाबले के आखिरी पलों में सुचिका ने कुछ कॉम्बिनेशन पंच लगाए। तेओ ने भी किक्स से जवाब दिया। अंतिम बजर बजने के बाद सुचिका ने अपनी प्रतिद्वंद्वी पर छलांग लगाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। रेफरी को दोनों खिलाड़ियों को अलग करना पड़ा। मुकाबला खत्म होने के बाद सुचिका फैसले से खुश नहीं थीं।

नियम क्या कहते हैं?

- एशियन MMA के नियमों के मुताबिक, ओवरटाइम में मुकाबला ड्रॉ होने की स्थिति में पहले यह देखा जाता है कि दोनों में से किसी खिलाड़ी को मुकाबले के दौरान चेतावनी मिली थी या नहीं।
- अगर दोनों खिलाड़ियों को बराबर संख्या में चेतावनियां मिली हैं, तो उन्हें दी गई सलाह/निर्देश को ध्यान में रखा जाता है।
- अगर दोनों खिलाड़ियों को दी गई सलाह भी समान है, तो मुकाबले से पहले उनका वजन देखा जाता है।
- अगर मुकाबले से पहले दोनों खिलाड़ियों का वजन भी समान हो, तो मुकाबले के बाद का वजन देखा जाता है।
- अगर मुकाबले के बाद का वजन भी समान रहता है, तो तीन सहायक रेफरी झंडे उठाकर विजेता का फैसला करते हैं।
- सुचिका के मामले में 700 ग्राम का वजन निर्णायक साबित हुआ। वजन के आधार पर तेओ ने मुकाबला जीत लिया और सुचिका फाइनल में पहुंचने से चूक गईं।
- आधिकारिक तौर पर इस नतीजे को 'ब्रेक टाई बाई वेट' यानी वजन के आधार पर बराबरी तोड़कर जीत के रूप में दर्ज किया गया।
- 36 वर्षीय सुचिका ने इसके बावजूद कांस्य पदक जीतकर भारतीय MMA में अपनी खास पहचान बनाई। उनकी संघर्ष और वापसी की कहानी युवा भारतीय MMA खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन सकती है।

कबड्डी में जापान की हालत की खराब

मुंबई कबड्डी में जापान को 49-23 से हराया

आइची नागोया । भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने भी एशियन गेम्स में जीत के साथ शुरुआत की। सुनील कुमार की कप्तानी में भारत ने मेजबान जापान को 49-23 से हराया। पूरे मुकाबले में भारतीय रेडर्स और डिफेंडर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत के रेडर्स ने शुरुआत से ही जापान के डिफेंस पर दबाव बनाए रखा। आशू मलिक ने एक ही रेड में जापान के तीन खिलाड़ियों को आउट कर सुपर रेड लगाई। उन्होंने लगातार भारत के लिए अंक जुटाए। वहीं, भारतीय डिफेंस ने जापान को पहले हाफ में दो बार ऑलआउट किया। भारत ने पहले हाफ का अंत 31-9 की बड़ी बढ़त के साथ किया।

दूसरे हाफ में भी भारत का दबदबा– दूसरे हाफ में जापान ने वापसी की कोशिश की और तेजी से अंक जुटाए। भारत ने पवन सहरावत, अर्जुन देशवाल और असलम इनामदार की तिकड़ी को मैदान पर उतारा। अर्जुन ने आते ही अंक हासिल किया और इसके बाद भारत एक बार फिर जापान को ऑलआउट करने में सफल रहा। अंतिम चरण में जापान के डिफेंस ने भारतीय रेडर्स की कुछ रेड को रोकने में सफलता हासिल की, लेकिन तब तक भारत बड़ी बढ़त बना चुका था।

अब दक्षिण कोरिया से भिड़ेगा भारत

जापान को हराने के बाद भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का अगला मुकाबला मंगलवार को दक्षिण कोरिया से होगा। टीम की कोशिश टूर्नामेंट में अपनी शानदार शुरुआत को आगे भी जारी रखने की होगी।

वार्म-अप में हुआ दर्दनाक हादसा

पिच रोलर की चपेट में आए इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर

खौफनाक वीडियो कैमरे में कैद

आइची नागोया । इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर एंड्रोस टाउनसेंड थाई लीग-1 के एक मुकाबले से पहले बेहद अजीब हादसे का शिकार हो गए। पीटी प्रचुआप के लिए खेलने वाले टाउनसेंड वार्म-अप के दौरान पिच रोलर की चपेट में आ गए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। टाउनसेंड शनिवार रात पट्टानी के खिलाफ मुकाबले की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान वह एक एरियल बैकहील करने की कोशिश में उछले और नीचे उतरते समय पिच रोलर के रास्ते में आ गए। बताया गया कि उसी समय वाहन का ड्राइवर दूसरी ओर देखने लगा था।

पैरों और कूल्हे के ऊपर से गुजरा रोलर– वीडियो में टाउनसेंड के पिच पर गिरने के बाद पिच रोलर को उनके ऊपर से गुजरते देखा जा सकता है। वाहन उनके पैरों और कूल्हे के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ गया। घटना के दौरान चीखें सुनाई दीं, जबकि आसपास मौजूद खिलाड़ी हैरान होकर सिर पर हाथ रखते नजर आए।

हालांकि, इस अजीब हादसे के बावजूद टाउनसेंड को गंभीर चोट नहीं आई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह रही कि वह बाद में अपनी टीम के लिए मैच में उतरने में भी सफल रहे।

टाउनसेंड ने खुद उड़ाया हादसे का मजाक– 35 वर्षीय टाउनसेंड ने घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दोबारा शेयर किया और इसके साथ लिखा, 'इसे ऐसा दिखाओ जैसे यह एक हादसा था।' उन्होंने इसके साथ हंसने वाली इमोजी भी लगाई। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी इस घटना को लेकर मजाक किया। टाउनसेंड ने पीटी प्रचुआप की 3-0 की जीत में इंजरी टाइम में बतौर स्थानापन्न मैदान पर कदम रखा।

इंग्लैंड के लिए 13 मैच खेल चुके हैं– टाउनसेंड इंग्लैंड के लिए 13 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं।

सविता पूनिया बनीं सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी

हॉकी इंडिया ने की 10 लाख रुपए देने की घोषणा

काकामिगाहारा । सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। हॉकी इंडिया ने सोमवार को भारतीय महिला हॉकी टीम की अनुभवी गोलकीपर सविता की सराहना की। इस खास उपलब्धि पर हॉकी इंडिया ने कहा कि यह सविता के करीब दो दशकों के अनुशासन, मेहनत और बेहतरीन नेतृत्व का नतीजा है। उनके शानदार योगदान को सम्मान देने के लिए हॉकी इंडिया ने उन्हें 10 लाख का नकद इनाम देने की घोषणा भी की। सविता ने भारत की पूर्व स्ट्राइकर वंदना कटारिया के 320 सीनियर इंटरनेशनल मैच खेलने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में इंडोनेशिया के खिलाफ भारत के पूल बी मैच के दौरान यह मुकाम हासिल किया और अपने शानदार करियर में एक और उपलब्धि जोड़ी।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चा

375 अनुमेय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का करें चयन: उप मुख्यमंत्री

एक सत बुलेटिन, रायपुर

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से वीसी द्वारा की वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन पर की चर्चाविकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जीरामजी) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों से संवाद किया। बैठक में योजनांतर्गत जिलों में स्वीकृत कार्यों, प्रगति तथा योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिला पंचायत प्रतिनिधियों से बारी-बारी संवाद करते हुए योजना के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा उनके सुझाव और जमीनी स्तर पर आ रही कठिनाइयों को जाना। उन्होंने सभी को वीबी-जीरामजी के अंतर्गत अब 375 प्रकार के अनुमय कार्यों में से स्थानीय आवश्यकता के अनुसार कार्यों का चयन एवं स्वीकृति के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में पर्याप्त संख्या में कार्य स्वीकृत किए गए है, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राम सभा के माध्यम से नए कार्य भी लिए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना में मजदूरी एवं सामग्री का 60रू40 अनुपात बनाए रखते हुए तथा जल संरक्षण से संबंधित कम से कम 30 प्रतिशत कार्यों को प्राथमिकता देते हुए ग्राम सभाएं आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य स्वीकृत कर सकती हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजना का लाभ ग्रामीणों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन करने पर जोर दिया। बैठक में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती ऋचा शर्मा ने पंचायतों में स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे, जिससे निर्माण कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। आयुक्त, विकसित भारतदृजीरामजी श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला पंचायत सदस्यों के योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा तकनीकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के विशेष प्रयासों तथा किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खेत सड़क और धरसा को भी अनुमय कार्यों में शामिल किया गया है। प्रदेश में बालिका शौचालय, मुक्तिधाम शेड तथा डिफंक्ट बोरवेल रिचार्ज जैसे कार्यों को प्राथमिकता से लिया जा रहा है। ग्राम पंचायतें अपनी स्थानीय आवश्यकता के अनुसार इन कार्यों का चयन कर सकती हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण (कन्वर्जेंस) से संबंधित भारत सरकार का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की प्रक्रिया में है। वहीं मनरेगा के शेष लंबित भुगतान के संबंध में भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया गया है।वीबी-जीरामजी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मानव संसाधन को मजबूत करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रथम चरण में 175 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें कार्यक्रम अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल के पद शामिल हैं तथा भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। इसके अतिरिक्त बस्तर, बीजापुर एवं नारायणपुर जिलों में 63 रोजगार सहायक पदों पर भर्ती की अनुमति भी प्रदान की गई है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अपने सुझाव साझा किए तथा मैदानी स्तर पर आ रही विभिन्न कठिनाइयों से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों एवं समस्याओं को आवश्यक कार्रवाई हेतु संकलित किया गया है।

पत्नी के निधन के बाद परिवार पर आया संकट, संबल योजना ने दिया सहारा

एक सत बुलेटिन, भिण्ड

घर के किसी सदस्य का निधन किसी भी परिवार के लिए गहरा आघात होता है, लेकिन जब परिवार की देखभाल का मुख्य सहारा भी वही व्यक्ति हो, तो परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। भिण्ड जिले के नगर परिषद मौ के वार्ड नंबर-03 लौहरपुरा निवासी श्री महेश यादव के परिवार के सामने भी कुछ ऐसी ही स्थिति उस समय उत्पन्न हुई, जब उनकी पत्नी का दिनांक 25 अप्रैल 2026 में निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद घर-परिवार की देखभाल की जिम्मेदारियां निभाना उनके लिए चुनौती बन गया। परिवार और बच्चों को वक्त देने के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, जिससे आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा था।आर्थिक संकट के इस दौर में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत श्री महेश यादव को जन विश्वास अभियान अंतर्गत आयोजित शिविर में अनुग्रह सहायता राशि दिए जाने हेतु स्वीकृति पत्र तैयार कर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला के हाथों प्रदान किया गया।संबल योजना अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह सहायता से परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने और विपरीत परिस्थितियों से उबरने में मदद मिलेगी।

करोड़ों की लागत से बन रहा बरही कॉलेज का भवन सवालों के घेरे में

वर्षों से कछुए की चाल चल रहा निर्माण

एक सत बुलेटिन, बरही/कटनी।

शासकीय महाविद्यालय बरही में छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए करोड़ों रुपये की लागत से कराया जा रहा अतिरिक्त भवन निर्माण अब अपनी धीमी रफ्तार और निर्माण व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य के बावजूद भवन का काम पूरा नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों का आरोप है कि निर्माण की गति के साथ-साथ गुणवत्ता, पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बरही महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण अतिरिक्त कक्षों और भवन की मांग लंबे समय से उठती रही थी। विद्यार्थियों की ओर से आंदोलन और महाविद्यालय प्रबंधन के पत्राचार के बाद इस दिशा में पहल हुई।

क्षेत्रीय लोगों ने भी विधायक संजय सत्येंद्र पाठक के समक्ष महाविद्यालय की भवन संबंधी समस्या रखी थी, जिसके बाद अतिरिक्त भवन निर्माण का रास्ता साफ हुआ। उम्मीद थी कि नया भवन बनने से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन निर्माण कार्य की धीमी गति ने अब पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से होने वाले किसी भी शासकीय निर्माण में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित जानकारी देने वाला सूचना बोर्ड तक दिखाई नहीं देने की बात सामने आ रही है। सामान्य तौर पर ऐसे बोर्ड पर स्वीकृत लागत, निर्माण एजेंसी, कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की अवधि, योजना अथवा मद, संबंधित विभाग तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी दर्ज रहती है। ऐसे में निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड का न होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच और तकनीकी निगरानी की व्यवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं, इसकी वास्तविक पुष्टि सक्षम तकनीकी अधिकारियों की जांच के बाद ही हो सकती है। ऐसे में मांग उठ रही है कि भवन निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। पूर्व में निर्माण स्थल से सामने आई तस्वीरों को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में निर्माण कार्य में निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया को लेकर आपत्तियां सामने आई थीं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 87वीं बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की 87वीं मंडल सम्मिलन बैठक मंडल मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश में आवासीय एवं व्यावसायिक सुविधाओं के विस्तार, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, भवनों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने तथा हितग्राहियों को राहत देने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए चिन्हित भूमि के उपयोग की प्रक्रिया को मंजूरी मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में मंडल की चिन्हित एवं स्वामित्व वाली भूमियों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए चार्जिंग स्टेशनों के डिजाइन, वित्त पोषण, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था के लिए लाइसेंस फीस मॉडल के तहत एजेंसी को भूमि उपयोग का अधिकार प्रदान करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। प्रमुख क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने होंडा क्यूसी3, होंडा सीबी 500 और रिफ्रेश्ड होंडा सीबी350 रेंज की कीमतों की घोषणा की

एक सत बुलेटिन, कटनी।

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (एचएमएसआई) ने आज नई होंडा क्यूसी3 और होंडा सीबी500 के साथ-साथ रिफ्रेश्ड होंडा सीबी350 रेंज की कीमतों की घोषणा की, जिसमें सीबी350, सीबी350आरएस और सीबी350सी शामिल हैं। यह घोषणा जुलाई 2026 में पेश किए जाने वाले 10-प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अगले चरण को दिखाती है, जो होंडा की मल्टी-पाथवे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और दुनिया के लिए मेक इन इंडिया कमिटमेंट को मज़बूत करती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्थानीय रूप से बनी हेरिटेज रोडस्टर और रिफ्रेश्ड मॉडर्न क्लासिक्स तक फैले ये प्रोडक्ट भारतीय ग्राहकों की अलग-अलग मोबिलिटी ज़रूरतों और राइडिंग की उम्मीदों को पूरा करते हैं। होंडा क्यूसी3 की कीमत 1,35,000 (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) रखी गई है और इसे शुरू में दिल्ली, आगरा, कटक, सूरत और कोल्लम में कुछ चुने

हुए ऑथराइज़्ड होंडा रेडविंग डीलरशिप के ज़रिए लाया जाएगा। एक स्मार्ट फ़ैमिली ईवी के तौर पर डेवलप की गई क्यूसी3 में 145 किमी सर्टिफाइड आईडीसी रेंज, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और 32-लीटर स्टोरेज है, जो परिवारों और रोज़ाना शहरी राइडर्स के लिए एक प्रैक्टिकल मोबिलिटी सॉल्यूशन देता है। क्यूसी3 चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी: मैट फोटॉन ग्रे मेटैलिक, पर्ल प्रेशियस व्हाइट, पर्ल शैलो ब्लू और पर्ल सायरन ब्लू। होंडा सीबी500 के एलॉय व्हील्स वेरिएंट की कीमत 2,75,000, स्पोक ट्यूबलेस वेरिएंट की कीमत 2,99,900, और स्ट्राइप वाले स्पोक ट्यूबलेस वेरिएंट की कीमत ?3,01,900 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) रखी गई है। यह देश भर में ऑथराइज़्ड होंडा बिगविंग डीलरशिप पर मिलेगी। भारत में बनी सीबी500, रेट्रो-स्पोर्टी डिज़ाइन, टॉर्क-रिच 501 सीसी इंजन कैरेक्टर, मज़बूत रोड प्रेज़ेंस और मॉडर्न राइडर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी के ज़रिए होंडा की रोडस्टर विरासत को भारतीय राइडर्स तक पहुंचाती है। सीबी500 पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, पर्ल इग्नियस ब्लैक, मैट स्टील सिल्वर मेटैलिक और रेबेल रेड मेटैलिक रंगों में उपलब्ध होगी। रिफ्रेश्ड होंडा सीबी350 रेंज की कीमत 1,95,200 (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) से शुरू हुई है। इसमें सीबी350, सीबी350आरएस और सीबी350सी शामिल हैं। इस रेंज में कलर ऑप्शन हैं, लेकिन कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इस सीरीज़ में होंडा के मॉडर्न क्लासिक पोर्टफोलियो का रिफाइनमेंट, रेट्रो-इंस्पायर्ड कैरेक्टर और पहले से मौजूद अपील बरकरार है।

जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनों का वितरण किया गया, आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया कदम

एक सत बुलेटिन, कटनी।

सतगुरु बाबा माधवशाह सेवा मंडल द्वारा 'मानव सेवा ही सच्चा धर्म' के संकल्प को साकार करते हुए निराश्रित एवं जरूरतमंद परिवारों की सेवा का सिलसिला लगातार जारी है। इसी सेवा श्रृंखला के तहत जरूरतमंद माताओं-बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सैकड़ों सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। बाबा माधवशाह भवन में आयोजित कार्यक्रम में जीवन मुक्त सतगुरु सांई ईश्वरशाह साहिब जी के पावन कर-कमलों से जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें प्रदान की गईं। सिलाई मशीन मिलने से महिलाओं को अपने हुनर को रोजगार से जोड़ने और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अवसर मिलेगा। सेवा मंडल द्वारा लंबे समय से जरूरतमंद एवं निराश्रित परिवारों के लिए विभिन्न सेवा गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

सतगुरु बाबा नारायणशाह साहिब जी द्वारा वर्ष 1960 में रोपा गया सेवा का बीज आज जीवन मुक्त सतगुरु सांई ईश्वरशाह साहिब जी की प्रेरणा से विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। सेवा मंडल के माध्यम से प्रतिमाह 200 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन एवं आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही शिक्षा, चिकित्सा, दिव्यांग सेवा सहित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यों के माध्यम से जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान सतगुरु सांई ईश्वरशाह साहिब जी ने मानव सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जरूरतमंदों के दुख-दर्द को समझना और उनके जीवन में खुशियां लाना ही सच्ची सेवा है। दूसरों के दुखों पर मरहम लगाने से मनुष्य को जीवन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। जरूरतमंदों की सेवा से मिलने वाली दुआएं अनमोल होती हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु साहिबानों की कृपा और सेवा की परंपरा से समाज के उत्थान का यह कार्य निरंतर आगे बढ़ रहा है।

कलेक्टर ने जनसुनवाई में एक आवेदक की समस्या का तत्काल किया निराकरण

भिण्ड। कलेक्टर भिण्ड श्री किरोड़ीलाल मीना ने कलेक्ट्रेट कार्यालय भिण्ड में आयोजित जनसुनवाई में जनसामान्य की शिकायतों को सुनकर उनके त्वरित, समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री एल.के. पाण्डेय, अपर कलेक्टर श्री राजन बी नाडिया एवं डिप्टी कलेक्टर श्री अखिलेश शर्मा द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं पर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई के दौरान 72 से अधिक आवेदन आए जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में ग्राम अमलेड़ी की निवासी श्रीमती राधा राजावत पत्नी श्री राधाकृष्ण ने बैसाखी दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तत्काल कलेक्टर द्वारा सामाजिक न्याय विभाग अधिकारियों को निर्देशित कर आवेदिका श्रीमती राधा राजावत को जनसुनवाई में ही बैसाखी मौके पर ही उपलब्ध कराई गई। जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपों का संधारण, पेंशन, सड़क दुघर्टना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं, बीपीएल राशन कार्ड एवं जमीन पर कब्जा से संबंधित आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके संबंध में आवेदक को भी कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश भी दिए।

फ्लैगशिप योजनाओं में लापरवाही पर निगमायुक्त सख्त

अवैध कॉलोनाइजरों पर एफआईआर और रात्रिकालीन सफाई के निर्देश

एक सत बुलेटिन, कटनी।

नगर पालिक निगम कटनी के एमआईसी सभाकक्ष में सोमवार को समय-सीमा (टीएल) प्रकरणों की समीक्षा बैठक निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में निगमायुक्त ने शासन की फ्लैगशिप योजनाओं, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़े मामलों में लापरवाही तथा अनावश्यक देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन, जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिकों की शिकायतों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। फोटो वाली स्टाइल में: बैठक के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए निगमायुक्त ने मुख्य बाजारों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। दुकानदारों और व्यावसायिक संस्थानों के बाहर डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखवाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने और कर्मचारियों की उपस्थिति की प्रतिदिन निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। राजस्व विभाग की समीक्षा में नामांतरण से जुड़े सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत ऑनलाइन और निर्धारित समय में निराकरण करने पर जोर दिया गया। राजस्व वसूली की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए निगमायुक्त ने दैनिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं सेवा

संकल्प अभियान के तहत स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता गतिविधियों को व्यापक स्तर पर संचालित करने को कहा गया। बैठक में सीवरेज, पेयजल आपूर्ति, डेयरी विस्थापन, सब्जी मंडी, मीट मार्केट और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जैसी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। निगमायुक्त ने डीपीआर, एनओसी, सक्षम स्वीकृति, निविदा, दर स्वीकृति और अनुबंध सहित सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रक्रियागत देरी के कारण किसी भी विकास कार्य की गति प्रभावित न हो। अवैध कॉलोनियों के मामलों में निगमायुक्त ने शेष प्रकरणों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। कोचिंग संस्थानों, निजी अस्पतालों, होटलों और मॉल्स में फायर सेफ्टी ऑडिट की धीमी प्रगति पर भी नाराजगी जताते हुए संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी करने तथा सुरक्षा मानकों की जांच में तेजी लाने को कहा गया। नियमों के विपरीत निर्मित भवनों में नियमानुसार कम्पाउंडिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ

नवकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और ऊर्जा भंडारण समग्र पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्णः मुख्यमंत्री

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश, पावर कट से पावर सरप्लस स्टेट अर्थात बिजली गुल से बिजली फुल राज्य बना है। हमारा प्रदेश आज देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जो अपनी ऊर्जा जरूरत से आगे बढ़कर देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखते हैं। वर्तमान में नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण केवल देश ही नहीं, अपितु समग्र पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज मध्यप्रदेश में 32 हजार मेगावाट की ऊर्जा क्षमता है, जिसमें से 30% हिस्सा क्लीन एनर्जी का है। मध्यप्रदेश, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण की किफायती खरीद विषय पर आयोजित ऑल इंडिया डिस्काम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ अवसर पर यह विचार व्यक्त किये।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का होटल मैरिएट में दीप प्रज्जवलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर पुस्तक 'सैलियंट पॉवर स्टैटिस्टिक्स वर्ष 2024-25 से 2025-26' विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विद्युत वितरण कम्पनियों के इस साझा मंच से ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों के ठोस समाधान निकलेंगे। इस अवसर पर ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ तथा ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह, सचिव उर्जा श्री विशेष गढ़पाले, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अजय गुप्ता, मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अमित तोमर विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अपने रिकॉर्ड स्वयं तोड़ रहा है मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में बिजली अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। राज्य सरकार बिजली की खपत बढ़ाने के साथ-साथ इसके उत्पादन और संधारण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक के साथ नई इकाईयां प्रारंभ की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में देश में 360 डिग्री बदलाव आया है। जब जी-20 सम्मेलन में ग्रीन-क्लीन एनर्जी का उत्पादन बढ़ाने और उपयोग का मुद्दा उठा, तो भारत ऐसा देश रहा, जिसने 50 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करके दिखाया है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से ही संभव हो पाया है।

सस्ती भरोसेमंद बिजली के लिए उपयोगी रहेगी कार्यशाला

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र अभूतपूर्व बदलाव से गुजर रहा है। हमारी जिम्मेदारी केवल बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करना नहीं, बल्कि उसे विश्वसनीय, टिकाऊ और किफायती बनाना है। भविष्य के लिए हमें सौर, पवन और ऊर्जा भंडारण का ऐसा संतुलित मिश्रण विकसित करना होगा, जिससे ऊर्जा संक्रमण की लागत न बढ़े और उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार न पड़े। ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल श्री आलोक कुमार ने कांफ्रेस के उद्देश्यों की जानकारी दी। प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री मनीष सिंह ने कॉन्फ्रेंस में पधारने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आभार व्यक्त किया। तकनीकी सत्रों में श्री आलोक कुमार तथा डायरेक्टर, ढ्ढ श्री एस. एन. कलिता ने ढ्ढ की गतिविधियों, अध्ययन परियोजनाओं, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए चल रही विभिन्न पहलों पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। प्रस्तुतियों में नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण की खरीद, मांग पूर्वानुमान, संसाधन पर्याप्तता, विद्युत खरीद में जोखिम संतुलन, दीर्घकालिक संसाधन नियोजन तथा वितरण कंपनियों के लिए लागत प्रभावी खरीद ढांचों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन डॉ. आशीष कुमार गोयल, तथा सचिव, ऊर्जा श्री विशेष गढ़पाले, ने भी अपने विचार साझा किए। प्रस्तुतियों में मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की पूरक मौसमी मांग आवश्यकताओं के आधार पर सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण के बेहतर उपयोग, साझा ऊर्जा परिसंपत्तियों के विकास, मांग प्रबंधन तथा लागत अनुकूलन की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

सहकारी बैंक के सीईओ 2 माह के अंदर अधीनस्थ सभी पैक्स का कर लें निरीक्षणः मंत्री विश्वास सारंग

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पैक्स का निरीक्षण 2 माह के अंदर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपने बैंक को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी की है। वह अनुशासन और एकरूपता के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं। बैंक में नवाचार कर एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। मंत्री श्री सारंग समन्वय भवन में सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। युवा अधिकारी पुराने अधिकारी-कर्मचारियों के अनुभव का लें लाभ मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सीईओ के पद पर नये एवं युवा अधिकारी पदस्थ हुए हैं। उनके लिये यह प्रशिक्षण कार्यक्रम लाभप्रद सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि पुराने अधिकारी-कर्मचारियों के अनुभव का लाभ भी उन्हें लेना चाहिये और उनका सम्मान भी बनाये रखना चाहिये। श्री सारंग ने कहा कि सीईओ अपने कलेक्टर से सतत सम्पर्क में रहें। साथ ही जिले के अधिकारियों से बेहतर समन्वय बनाये रखें। उन्होंने कहा कि सुव्यवस्था स्थापित करने के लिये अपने अधीनस्थ पैक्स को चैनेलाइज करें।

मंत्री परमार की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक हुई

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भोपाल स्थित मंत्रालय में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल की सामान्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में विद्यार्थियों के हित, शैक्षणिक गुणवत्ता, संस्थान की अधोसंरचना तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, सुरक्षित परिसर और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के प्रारंभ में पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन एवं कार्यवाही विवरण प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों की सुविधाओं और सुरक्षा को प्राथमिकता बैठक में मंत्री श्री परमार ने संस्थान में विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन उपकरण स्थापित करने का विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित

गतिविधियों को सामान्य बजट भाग-1 में शामिल करते हुए वार्षिक गतिविधियों के लिए 50 हजार रुपए का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के विशेष अन्य आकस्मिक व्यय में भी 10 लाख रुपए की वृद्धि की गई, जिससे संस्थान की विभिन्न गतिविधियों का सुचारु संचालन किया जा सकेगा। सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय भवन की व्यवस्थाओं में सुधार तथा अध्ययन कक्ष को वातानुकूलित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में मेजर एवं माइनर विषयों के स्वैप तथा डबल मेजर के लिए विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क के प्रस्ताव को भी सामान्य परिषद ने मान्यता प्रदान की।

भोपाल में 21 पशु पकड़े, सात बीमार-घायल आसरा भेजे

भोपाल। नगर निगम ने मंगलवार को सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर खुले में घूम रहे पशुओं को हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम के गोवर्धन परियोजना शाखा के अमले ने विभिन्न क्षेत्रों से 21 पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस भेजा, जबकि बीमार और घायल सात पशुओं को आसरा पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। हांका पार्टी ने 15 पशुओं को सड़कों से हटाया। निगम के अनुसार मालीखेड़ी, संत हिरदाराम नगर, प्रेमपुरा, खटलापुरा, शाहपुरा, हथाईखेड़ा, रानी कमलापति विसर्जन घाट, कमला पार्क, आनंद नगर, भारत नगर, निजामुद्दीन कॉलोनी, इंद्रपुरी, करोंद, भानपुर, बैरागढ़, लालघाटी, कोलार रोड और चूना भट्टी सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इसके अलावा निगम अमले ने खजूरीकलां कांजी हाउस से 18 पशुओं को रामकृष्ण गौशाला भेजने की कार्रवाई भी की। निगम के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की बैठक संपन्न आज धरना एवं 28-30 सितंबर को बैंक हड़ताल

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनर तले आज भोपाल में बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी आंदोलन की तैयारियों, कार्यक्रमों एवं संगठनात्मक रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक का संचालन वरिष्ठ कामरेड वीरू शर्मा ने किया। बैठक की अध्यक्षता एआईबीओसी के सचिव दिनेश झा ने किया, जबकि एआईबीओसी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सुबीन सिन्हा ने उपस्थित साथियों का स्वागत किया। बैठक में सर्वसम्मति से आगामी आंदोलन को प्रभावी एवं व्यापक बनाने के लिए सभी संगठनों की एकजुट भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर संगठन लगातार संघर्षरत हैं और आगामी कार्यक्रमों में अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित की

जाएगी। 23 सितंबर को भोपाल में धरना प्रदर्शन यूएफबीयू के आह्वान पर 23 सितंबर 2026 को प्रेस कॉम्प्लेक्स, पंजाब नेशनल बैंक, होशंगाबाद रोड, भोपाल में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

इसमें बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में शामिल होंगे। 28, 29 एवं 30 सितंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल बैठक में बताया गया कि यूएफबीयू के आह्वान पर 28, 29 एवं 30 सितंबर 2026 को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल आयोजित की जाएगी। हड़ताल को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। बैठक में उपस्थित नेताओं ने सभी बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आगामी कार्यक्रमों में एकजुट होकर सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। यूएफबीयू के संयुक्त आंदोलन को लेकर बैंकिंग संगठनों में व्यापक तैयारी और लामबंदी का दौर जारी है।

स्वर्गीय माहेश्वरी का जीवन राष्ट्रसेवा और निर्भीक पत्रकारिता की प्रेरणाः उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने भोपाल में स्वर्गीय श्री रामगोपाल माहेश्वरी जी के नाम पर मार्ग की नामपट्टिका का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय श्री माहेश्वरी के राष्ट्र और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि यह सभी के लिए गौरव और आनंद का क्षण है। कुछ व्यक्तित्व केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होते हैं और उनके विचार एवं आदर्श आने वाली पीढ़ियों को दिशा देते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि स्वर्गीय श्री माहेश्वरी ने स्वतंत्रता से पहले प्रेस की स्थापना की। उस दौर में जब देश स्वतंत्रता आंदोलन के कठिन दौर से गुजर रहा था, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर निर्भीकता से पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनका जीवन राष्ट्रहित, सामाजिक सरोकार और पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी है।

यह आवश्यक है कि जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से सामने लाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सजग एवं निर्भीक भूमिका निभाएं। स्वर्गीय श्री माहेश्वरी ने अपने कार्यों से पत्रकारिता के इसी दायित्व को मजबूत किया। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मार्ग का नाम स्वर्गीय श्री माहेश्वरी के नाम पर होना उनके योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इस मार्ग से गुजरने वाले लोग उनके नाम और योगदान से परिचित होंगे। जब-जब कोई व्यक्ति इस मार्ग से निकलेगा, स्वर्गीय श्री माहेश्वरी के आदर्शों और राष्ट्रसेवा के प्रति उनके समर्पण का स्मरण होगा।

भाजपा ने सौपी माधवेन्द्र को दतिया की कमान

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दतिया विधानसभा के उपचुनाव में मिली पराजय और जिला कार्यकारिणी को भंग करने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि आखिर दतिया में किसे कमान सौपी जाएगी। आखिरकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इससे पर्दा उठा दिया है और माधवेन्द्र सिंह परिहार को कमान सौप दी है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बुधवार को माधवेन्द्र सिंह परिहार के नाम का ऐलान कर दिया। माधवेन्द्र आरएसएस की पृष्ठभूमि के नेता है दतिया उपचुनाव के दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी ने भी इन पर भरोसा जताया था।

युवाओं के समग्र विकास के लिए योजनाओं में समन्वय और अद्यतन डाटा जरूरी : सचिव रघुराज एम आर

■ एक सत बुलेटिन, बैरसिया।

युवाओं को शिक्षा, कौशल, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए विभागीय योजनाओं में बेहतर समन्वय, विश्वसनीय डाटा और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को युवाओं के समग्र विकास का प्रभावी समन्वित मंच बनाया जाए। यह निर्देश तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री रघुराज एम आर ने मंगलवार को मंत्रालय में मिशन की अंतरविभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में भा-वाणी, युवा संवाद, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईके, पर्यावरण संरक्षण, एकलव्य एवं कन्या शिक्षा परिसर, पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस और सांदीपनि विद्यालय सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लक्ष्यों एवं डाटा की समीक्षा की गई। सचिव श्री रघुराज ने सभी विभागों को योजनाओं की अद्यतन एवं प्रमाणिक प्रगति का डाटा समय पर उपलब्ध कराने तथा ऑनलाइन डाटा को निरंतर अद्यतन रखने के लिए एपीआई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल डाटा के प्रभावी उपयोग से योजनाओं की निगरानी और उनके परिणामों का आकलन अधिक सटीकता से किया जा सकेगा। श्री रघुराज ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा प्रत्येक वालंटियर को युवाओं से जोड़कर साक्षरता और क्षमता विकास को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। पंचायत, ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास विभाग के सहयोग से 'युवा संवाद' और 'युवा संगम' जैसी गतिविधियों को प्रभावी रूप से संचालित करने पर भी जोर दिया गया।

स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की अंतरविभागीय बैठक में योजनाओं की प्रगति और कार्य-प्रदर्शन संकेतकों की समीक्षा

कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन एवं आंशिक निरस्तीकरण रहेगा

बीना स्टेशन पर कार्य के कारण भोपाल–जोधपुर–भोपाल एक्सप्रेस के मार्ग में संशोधन

■ एक सत बुलेटिन, भोपाल

उत्तर मध्य रेलवे के अगासोद एवं पश्चिम मध्य रेलवे के बीना के बीच तीसरी रेल लाइन की कनेक्टिविटी के लिए बीना स्टेशन पर प्री-एनआई एवं एनआई कार्य के चलते पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधित परिचालन व्यवस्था के अनुसार कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन, शॉर्ट टर्मिनेशन/शॉर्ट ओरिजिनेशन तथा आंशिक निरस्तीकरण किया जाएगा। इन ट्रेनों के मार्ग में संशोधन 1. गाड़ी संख्या 14814 भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक कुल 15 फेरे अपने निर्धारित मार्ग की बजाय संशोधित मार्ग से संचालित होगी। इस अवधि में ट्रेन का संशोधित मार्ग भोपाल-संत हिरदारामनगर-मक्सी-रूठियाई-कोटा रहेगा। पूर्व में अधिसूचित मार्ग में आंशिक संशोधन किया गया है। 2. गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर-भोपाल एक्सप्रेस दिनांक 01 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026

तक कुल 15 फेरे अपने निर्धारित मार्ग की बजाय संशोधित मार्ग से संचालित होगी। इस अवधि में ट्रेन का संशोधित मार्ग कोटा-रूठियाई-मक्सी-संत हिरदाराम नगर-भोपाल रहेगा। 1.गाड़ी संख्या 51886 दमोह-बीना पैसेंजर दिनांक 20 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक बीना मालखेडी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी एवं बीना मालखेडी स्टेशन 11.45 बजे पहुँचेगी। (कुल 26 ट्रिप) 2.गाड़ी संख्या 51883 बीना-ग्वालियर पैसेंजर पैसेंजर दिनांक 20 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक बीना मालखेडी स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा बीना स्टेशन को फ्लाईओवर के माध्यम से बायपास करते हुए संचालित की जाएगी बीना मालखेडी स्टेशन से 11.45 बजे प्रस्थान करेगी । (कुल 26 ट्रिप) 3.गाड़ी संख्या 61612 रूठियाई-बीना मेमू दिनांक 18 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक महादेवखेड़ी स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा महादेवखेड़ी-बीना के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। इस अवधि में गाड़ी संख्या 61612 रूठियाई-बीना मेमू को रूठियाई से 90 मिनट रीशैड्यूल रहेगी। (कुल 12 ट्रिप) 4.संख्या 61625 बीना-रूठियाई मेमू दिनांक 18 सितंबर से 29 सितंबर 2026 तक महादेवखेड़ी से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा बीना-महादेवखेड़ी के मध्य आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। (कुल 12 ट्रिप) 5.गाड़ी संख्या 11271 इटारसी-भोपाल एक्सप्रेस दिनांक 09 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक दमोह स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी तथा दमोह-भोपाल के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। (कुल 07 ट्रिप) 6.गाड़ी संख्या 11272 भोपाल-इटारसी एक्सप्रेस दिनांक 09 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक दमोह से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा भोपाल-दमोह के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। (कुल 07 ट्रिप) रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि उक्त अवधि में यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन के संचालन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर यात्रा की योजना बनाएं।

स्वामी **एक सत प्रयास जनकल्याण समिति** के लिए मुद्रक प्रकाशक एवं **सम्पादक अमित शर्मा** द्वारा 401, जीवन छाया अपार्टमेंट, राइट टाउन, जबलपुर (मप्र) पिन: 482004 से प्रकाशित एवं पीजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर, मध्य प्रदेश 482002 से मुद्रित। पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार।
RNI-MPHIN/2019/78787, स्थानीय संपादकः विक्रम सिंह। E-mail:eksatbulletin@gmail.com, मार्केटिंग एवं अन्य जानकारी हेतु हेड ऑफिस संपर्क करें- ए-1 माचना कॉलोनी, शा.राजीव गांधी हाई स्कूल शिवाजी नगर 6 नंबर बस स्टाप पास भोपाल। फोन: 0755-4515227, मोबाइल: 9893311784